fo"k; lwph

2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस घोटाला.. 5

बंदेमातरम् पर विवाद

आहत् करता है....................
एम.एन. बुच...................... 6

राष्ट्र–विरोधी फतवा
बल्देव भाई शर्मा.............. 8

कांग्रेसी अलगाववाद
मुख्तार अब्बास नकवी...... 10

झारखण्ड विधानसभा चुनाव

साक्षात्कार : करुणा शुक्ला...... 11
रघुबर दास.......... 13

विशेष रिपोर्ट............................. 14

लेख

लूट के लोकतांत्रिक तरीके
–राजीव सचान................ 16

नक्सली हिंसा की चुनौती
–हृदयनारायण दीक्षित........ 18

अन्य

बेलगाम महंगाई....................... 21

मध्य प्रदेश कार्यसमिति बैठक.. 23

दिल्ली– जनता के साथ धोखा..26

भाजपा सीए सेल बैठक.......... 28

भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ धरना... 30

सम्पादक

çHkkr >k] lkln

सम्पादक मंडल

lR;iky

d- d- 'kek

latho dekj flUgk

पृष्ठ संयोजन

/keZUæ dkS'ky

सम्पर्क

Mk- eqdthZ Le`fr U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887
lnL;rk gsrq % +91¼11½&23005700

सदस्यता शुल्क

okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

lEikndh;

सबसे बढ़िया बात क्या है? अपने साथ जो बुराई करे, उसके साथ भी भलाई करना।

-नीतिशतक

‘जब संगठन सर्वोपरि है’ फिर ऐसा क्यों.........?

nशभर में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थकों का मन पिछले कुछ दिनों से आहत है। पराजय की मार झेलने के बाद भी उनमें निराशा और हताशा का ऐसा दौर नहीं देखा गया। परन्तु आज सबके मुंह पर एक ही बात सुनने में आ रही है कि ‘‘हम जवाब क्या दें’’?

एक बार हम पीछे मुड़कर देखें, तो जिस तरह की पराजय सन् 2004 में हुई थी, वैसी ही इस समय भी हुई। अंतर इतना ही था कि सन् 2004 में भाजपानीत एनडीए की सरकार थी और सन् 2009 में भाजपा विपक्ष में थी। उस समय भी महाराष्ट्र, अरूणाचल और हरियाणा में भाजपा को जीत हासिल नहीं हो पाई थी। इस बार भी यही हुआ। पर देखने में आ रहा है कि उस समय और इस समय के माहौल में जमीन–आसमान का अंतर है। आज हम सभी को इस बात की चिंता करनी होगी कि भाजपा की साख और धाक को धक्का न लगे। भाजपा आजादी के बाद की वह पार्टी है जो विपक्ष में रहते हुए सत्ता के दरवाजे तक पहुंची। भाजपा वह पार्टी है जो अभी भी पांच–सात राज्यों में सरकार चला रही है। ‘भाजपा’ वह पार्टी है जिसके नेता जनसंघ की स्थापना करने के बाद ‘‘कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है’’ के लिए शहीद हुए। भाजपा वह पार्टी है जिसके नेता पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्ममानव दर्शन देशवासियों के समक्ष रखा। भाजपा भारतवासियों के मन की पार्टी है। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसकी सर्वधर्म समभाव और पंथनिरपेक्षता में अटूट आस्था है।

भाजपा कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, समर्थकों और समान विचारधारा वाले संगठनों के सहयोग से खड़ी पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चलने का गर्व भाजपा को है। साथ ही धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता में भाजपा का पूर्ण विश्वास है।

भाजपा पिछले कई वर्षों से भारतीय राजनीति के केन्द्र–बिन्दु में है। भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा तक की राजनीतिक यात्रा में हमारे पुरखों की वर्षों तक पुण्याई रही है। तिल–तिल जलकर लोगों ने जनसंघ का ‘दीया’ जलाया और ‘‘कमल’’ को गांव–गांव तक पहुंचाया।

पिछले तीन–चार वर्षों में भाजपा की साख और धाक में निरंतर बढोत्तरी हो रही थी। यही कारण था कि एक समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ‘‘भाजपा एक बढ़ती हुई पार्टी है।’’ पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने कांग्रेस को राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारी पटकनी दी। बिहार में लालू राज समाप्त हुआ। भाजपा गठबंधन जीता। झारखंड में भाजपा सरकार थी। कांग्रेस ने साजिश की पर उस समय कांग्रेस की नहीं चली। भाजपा

नेतृत्व सड़कों पर उतरा और संविधान की आन बची। इतना ही नहीं तो पंजाब, हिमाचल एवं उत्तराखंड जहां कांग्रेस की सरकारें थी, भाजपा ने उनसे ये राज्य छीना। आज इन राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है।

आगे बढ़ें तो गुजरात का विधानसभा चुनाव तो भाजपा की प्रतिष्ठा और नाक बन गई थी। कड़े संघर्षों के बाद अंततः भाजपा जीती। श्री नरेन्द्र मोदी ने पुनः सरकार बनाकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ा, जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को जेल भेजेंगे।

भाजपा को लोग उत्तर भारतीयों की पार्टी कहते थे, पर कर्नाटक में भाजपा का परचम लहराया। दक्षिण में भाजपा के लिए द्वार खोलने वाले श्री येदुयुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह मिथक भी टूटा। नागालैंड में गठबंधन की सरकार से पूर्वोत्तर राज्यों में आशा जगी।

यह बात भी छुपी नहीं है कि हमारी उत्तर प्रदेश की पराजय अच्छी नहीं थी। राजस्थान और दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणामों से देश आहत हुआ। अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें दिल्ली में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। राजस्थान में भी हालत पतली रही। उल्टे राजस्थान को लेकर अभी हाल ही में जो दृश्य उत्पन्न हुआ उससे देशभर के कार्यकर्ताओं का मन दुखी हुआ। आखिर बिना अनुशासन और दल की एकता के हम कहां रहेंगे? क्या हम सभी यह नहीं जानते कि दिल्ली में जनता भाजपा के पक्ष में थी। फिर विधानसभा चुनाव क्यों हारे? दिल्ली हमारी थाती रही है। दिल्ली देश को दम देती थी। आज यह हो गया कि दिल्ली में हमारे पास लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। आखिर क्या भाजपा नेतृत्व हार के कारणों को नहीं जानती? भाजपा जनता के प्रति जवाबदेह है, अतः स्वतः ही भाजपा नेतृत्व की जिम्मेदारी बन जाती है। अभी हाल ही में जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है, क्या वह किसी अनुशासित पार्टी का हिस्सा कहा जाएगा कदापि नहीं? हम कमजोर कहां है? हमारी कमजोरी क्या है? समय रहते उन बातों से दूर होना होगा जो भाजपा को कमजोर करती हैं। दोषारोपण से भी काम नहीं चलेगा, पर नेतृत्व को यह तो समझना ही होगा कि हालात किन कारणों से यहां तक पहुंच रहे है? ■

'जीवेम् शरदः शतम्'

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी 82 साल के हो गए। उनके जन्म दिवस (8 नवम्बर) पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली, वरिष्ठ नेता श्री एम. वेंकैया नायडु, लोकसभा में उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में उप-नेता श्री एसएस अहलूवालिया और पार्टी के सभी उपाध्यक्षों एवं महासचिवों तथा राष्ट्रीय सचिवों ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

'कमल सन्देश' के सम्पादक श्री प्रभात झा, सांसद (राज्यसभा) तथा सम्पूर्ण 'कमल सन्देश' परिवार लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है और कामना करता है कि वे दीर्घायु हों एवं हमारा मार्गदर्शन करते रहें।

दूरसंचार के अरबों रूपए के घोटाले में प्रधानमंत्री की टिप्पणी क्यों?

26 अक्टूबर को भाजपा के महासचिव तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता द्वारा 2–जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस घोटाले पर जारी वक्तव्य

सीबीआई ने 2007 में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए 2–जी स्पैक्ट्रम लाइसेंसों के आवंटन के बारे में बाकायदा एक मामला दर्ज किया है। दूरसंचार विभाग के कार्यालयों ने कई स्थानों की तलाशी ली है और विभिन्न दस्तावेज पकड़े हैं। अभी जब खोजबीन का कार्यक्रम चल ही रहा था और स्पष्ट रूप से दूरसंचार मंत्री ए. राजा पर उंगली उठ रही थीं तभी प्रधानमंत्री ने एक बयान देकर कह दिया कि दूरसंचार मंत्री ए. राजा के खिलाफ लगे आरोप सही नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो कुछ भी विपक्षी दल कह रहे हैं, वह सदा ही सही नहीं होता है। ए. राजा के इस बयान पर कि जो कुछ भी घट रहा था उसकी सूचना प्रधानमंत्री को दे दी गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ''मैं अपने कैबिनेट सहयोगी की बात को सार्वजनिक मुद्दा नहीं बनाऊंगा।'' साफ है प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सहमति अथवा असहमति प्रगट नही कर पा रहे हैं।

श्री ए. राजा और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोप एक दम स्पष्ट हैं। 2007 में एक खुली लाइसेंस व्यवस्था की सिफारिश की गई। दूरसंचार लाइसेंसों के लिए आवेदन मंगाए गए जिनकी आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2007 रखी गई। पहला आरोप यही है कि जब आवेदनों को मंगाने की अंतिम तारीख 1.10.2007 रखी गई थी, तब एक 'कट आफ' तारीख 25.9.2007 बना दी दी गई और 25.9.2007 तथा 1. 10.2007 के बीच प्राप्त आवेदनों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया और उन पर विचार नहीं किया गया। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम बदल दिए गए। सभी मित्र आवेदनों को जिनमें अधिकांशतः 'रियल एस्टेट' अर्थात् अचल सम्पत्ति कम्पनियों के थे, परामर्श दिया गया कि वे अपने आवेदन 25.9.2007 को या उससे पहले भेज दें। जैसा कि प्रधान मंत्री की टिप्पणी है, यह आरोप विपक्षी दलों का नहीं है। यह तो अब दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है, जिसने 'कट आफ' तारीख के निर्धारण को रद्द कर दिया है, जिसके कारण बहुत से अनुभवी आवेदनों को छोड़ दिया गया और अपेक्षतया कम अनुभवी पार्टियों को 9 लाइसेंस जारी कर दिए गए।

अगला आरोप लाइसेंसों के सम्बंध में ली जाने वाली राशि से है और उन 9 आप्रेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटन से ताल्लुक रखती है। लाइसेंस केवल सेवा आप्रेट करने का हक देती है। प्रत्यक्ष रूप से आप्रेशन का कामकाज स्पेक्ट्रम के आवंटन के बाद ही किया जा सकता है। दोनों मिलाकर प्रत्येक आप्रेटर से 1650 करोड़ रूपए की कीमत पर आवंटन किया गया। यह कीमत 2007 के बाजार मूल्य लाइसेंस आधार पर नहीं ली गई, बल्कि यह 2001 में हुई नीलामी के आधार पर ली गई जो 2001 की कीमत के आधार पर निश्चित हुई थी इस प्रकार 2001 की कीमत पर बहुमूल्य सार्वजनिक सम्पत्तियों का आवंटन 2007 में किया गया। मंत्री महोदय का यह कहना कि 'ट्राई' की सिफारिश यह थी। कि 2001 में निर्धारित 'एंट्री फी' अर्थात् प्रवेश शुल्क लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वास्तविक कीमत नहीं है। संभवतः 'बाजार तंत्र' के माध्यम से इसका पुनः आकलन किया जाना चाहिए। जो भी हो, साधारणतः किसी भी सरकारी सम्पत्ति को नीलामी करके बेचा जाना चाहिए। इस दौरान तो दूरसंचार का बाजार कहीं बड़े स्तर पर विकसित हो चुका है। स्पष्ट है कि सरकार और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। इस मामले में हानि की मात्रा का सहज ही निर्धारण किया जा सकता है। आवंटियों ने आवंटन के बाद सेवा प्रदान करने का काम किया ही नहीं। आंवटियों को जो भी स्वामित्व में मिला वह तो एक 'शैल' अर्थात् आवरण कम्पनी मात्र था और गारंटीकृत स्पेक्ट्रम था। इन्हें सरकार की 74 प्रतिशत एफडीआई मिली और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदार/संयुक्त उद्यम प्राप्त हो गए। रातोंरात ये कम्पनियां 200 बिलियन डालर मूल्य की बन गई और कम से कम तीन लाइसेंसधारियों ने बहुत बड़ी मात्रा में अपनी ईक्विटियों को ओवरसीज पार्टनरों को 6000–7000 करोड़ रूपए में बेच दिया। यदि प्रत्येक स्पेक्ट्रम का मूल्य 9000 करोड़ रूपए से अधिक था तो स्पष्ट है कि सरकार को प्रत्येक

...शेष पृष्ठ 9 पर

आहत करता है वंदेमातरम् का विरोध

,e-,u- cp

Hkk रत के संविधान के पहले शब्द हैं, 'हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगी.त, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।' पंथनिरपेक्षता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, जिसका भावार्थ अनुच्छेद 25 में दिया गया है। इस अनुच्छेद के अधीन लोक–व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार–प्रसार करने का समान हक होगा। इसके साथ ही हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का आदर करे।

इस परिप्रेक्ष्य में यह स्मरण करना आवश्यक है कि संविधान सभा ने संकल्प कर यह निर्धारित किया था कि जहां तक राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का प्रश्न है, इसका निर्णय सभापति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पर छोड़ा जाए। 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम निर्णय लिया जो संविधान सभा ने स्वीकार किया। उनके शब्द थे, ष्जन–गण–मन के नाम से जाने जाने वाले शब्दों और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम्? जिसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जन–गण–मन के बराबर आदर का पात्र होगा।' भारत में विधिवत एक राष्ट्रगान है, जन–गण–मन और उसके बिल्कुल समकक्ष राष्ट्रगीत है, वंदेमातरम्?। 25 अगस्त, 1948 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था, 'वंदेमातरम्' स्पष्टतः और निर्विवाद रूप से भारत का प्रधानतम राष्ट्रीय गीत है, जिसकी एक महान ऐतिहासिक परंपरा है और जो हमारे स्वाधीनता संग्राम से घनिष्ठतः संबद्ध है। इसकी यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी और कोई दूसरा गीत इसे विस्थापित नहीं कर सकता। यह हमारे संघर्ष की स्थिति और मार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही उसकी पूर्ति नहीं करता हो। वंदेमातरम्? सदैव बेजोड़ राष्ट्रगीत बना रहेगा।'

जन–गण–मन के तीन पद हैं परंतु केवल प्रथम पद ही हमारा राष्ट्रगान है। इसी प्रकार राष्ट्रगीत के भी तीन पद्य है, जिनमें से केवल पहला पद ही राष्ट्रगीत है। इस पहले पद का अर्थ है कि हम हमारी मातृभूमि की वंदना करते हैं (पूजा नहीं), यह भूमि शीतल जल और स्वादिष्ट फलों से भरपूर है, इसकी मिट्टी चंदन के समान शीतलता प्रदान करती है, इसकी भूमि अति उपजाऊ अथवा सरखेज है। इसकी रात चांदनी से चमकती है और यह फूलों से सुशोभित है। अपनी प्रा.तिक संपदा के कारण हमारी मां मीठे कंठ से बोलती है, और सबको आनंद का वरदान देती है। इन शब्दों में एक भी ऐसा नहीं है जो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हो या ऐसी कोई बात कहता हो जो इस्लाम के विरुद्ध हो। यदि अल्लामा इकबाल की नज्म, 'सारे जहां से अच्छा' जो हमारा दूसरा कौमी तराना है, से तुलना करें तो पाएंगे कि अल्लामा इकबाल के गीत और राष्ट्रगीत के शब्द लगभग एक ही हैं। 'सारे जहां से अच्छा' हमसे कहता है कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलिस्तां या बाग है, जहां हमारा दिल है। वे लिखते हैं कि हिंदुस्तान की गोदी में हजारों नदियां खेलती हैं। जिनकी वजह से हमारे गुलशन या बगीचे लहलहा रहे हैं। यह वह देश है, जहां मजहब किसी से बैर रखना नहीं सिखाता, क्योंकि हम सब हिंदी हैं और हिंदुस्तान हमारा वतन है। इकबाल के दिल में हिंदुस्तान के लिए दर्द है! परंतु इकबाल को पाकिस्तान, जो एक इस्लामी जम्हूरियत है, का राष्ट्रकवि माना जाता है।

मुसलमान अपने बुजुर्गों की आदर करते हैं, उनके सामने झुककर सलाम करते हैं, उनके आदेश की तामील करते हैं, अपने पिता को अब्बा हुजूर और मां को अम्मी जान कहते हैं। क्या उनका यह आचरण कुफ्र है, और देवबंद के उलेमा इसके विरुद्ध भी फतवा जारी करेंगे।

यह भूमिका इसलिए कि हाल में दारूल उलूम देवबंद के परिसर में जमायत–ए–उलेमा–ए–हिंद ने जो संकल्प किए हैं, जो फतवे दिए हैं, उनसे मैं अत्यंत चिंतित हूं कि क्या मुस्लिम समाज के ये तथाकथित नेता वास्तव में अपने आप को भारतीय समझता है या नहीं। नागरिकता, विशेषकर एक पंथनिरपेक्ष संविधान से सुरक्षा प्राप्त करते हुए, उस पंथनिरपेक्ष देश के कानूनों के आधार पर समान नागरिक के सारे अधिकार प्राप्त करते हुए, किसी भी संप्रदाय, धर्म या विचार के नागरिक को यह हक नहीं है कि वह उस देश के सिद्धांत और संविधान के विरुद्ध कोई भी निर्णय ले या काम करे। धर्म–स्वातंत्र्य का अर्थ यह नहीं है कि देश के मूलभूत सिद्धांतों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाए कि कुछ लोग इन सिद्धांतों को अपने धर्म के विरुद्ध समझते हैं। वैसे स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस्लाम में मां का स्थान उतना ही ऊंचा है, जितना कि हिंदू धर्म या ईसाई धर्म में है। अपनी मां का आदर करने उसके आगे सिर झुकाने का अर्थ यह नहीं हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और की

इबादत की जा रही है। मुसलमान अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, उनके सामने झुककर सलाम करते हैं, उनके आदेश की तामील करते हैं, अपने पिता को अब्बा हुजूर और मां को अम्मी जान कहते हैं। क्या उनका यह आचरण कुफ्र है, और देवबंद के उलेमा इसके विरुद्ध भी फतवा जारी करेंगे।

पाकिस्तान का राष्ट्रगीत उस देश की तारीफ करता है। अजरबेजान, जिसकी अधिकांश आबादी मुस्लिम है, का राष्ट्रगीत अजरबेजान को अपनी मां कहता है और उसके शब्द हैं, 'इस मां ने अजरबेजानियों के जीवन को एक अर्थ दिया है।' सऊदी अरब का राष्ट्रगीत आश–उल–मलिक का मतलब है हमारे बादशाह चिरंजीवी हों।' इस प्रकार कुवैत, ब्रुनेई और जॉर्डन के राष्ट्रगीतों में भी वहां की राजशाही के लिए दुआ मांगी गई है और उन्हें सर्वोपरि माना गया है। क्या यह एक मनुष्य की स्तुति नहीं है। किसी उलेमा ने इसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई?

यह तो निर्विवाद है कि भारत के मुस्लिम राष्ट्रभक्ति में किसी से कम नहीं हैं और राष्ट्र के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम अगाध है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके तथाकथित धार्मिक नेता इन वफादारों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि जब वे ऐसे फतवे जारी करते हैं जो इस गणराज्य के मूलभूत सिद्धांतों के विरूद्ध हैं तो उनके देशप्रेम पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

इस तरह की संकीर्ण सोच वाले लोग आखिर चाहते क्या हैं जो राष्ट्रीयता के मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं? सहिष्णुता में भारत विश्व का सबसे अग्रगण्य देश है और हम सबको अपनाते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, हर विचारधारा का आदर करते हैं। हमारा कोई नागरिक राष्ट्रगीत गाता है या नहीं हम इसकी जासूसी नहीं करते। परंतु यह देश इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि चंद लोग यह प्रतिबंध लगा दें कि उनके धर्म के अनुयायी राष्ट्रगान गाएंगे ही नहीं और यदि गाएंगे तो यह कुफ्र माना जाएगा। ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है। ■

(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और समाजकर्मी हैं।)

सरकार दूर-दराज क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए वचनबद्ध : निशंक

राज्य सरकार दूर–दराज क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछाने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए विजन 2020 के अन्तर्गत ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सरकसर का प्रयास है कि चारधाम यात्रा मार्गों को और अधिक सुगम बनाया जाय, साथ ही मोटर मार्गों के विस्तारीकरण कार्यों में तेजी लाये। 2013 तक चारधाम यात्रा मार्गों को चार लेन किया जाय। राज्य में मोड़ मार्गों को सुगम बनाने वे इनके विस्तारीकरण कार्य में सीमा सड़क संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने सचिवालय में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेट. जनरल एम.सी. बधानी से भेंट के दौरान कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. निशंक ने सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तराखण्ड में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने महानिदेशक से कहा कि यह क्षेत्र दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में होने के कारण संवेदनशील है तथा यहां की सीमाओं पर निर्माण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने उनके द्वारा संचालित प्रदेश में निर्माणधीन परियोजनाओं में सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रदेश में सीमा सड़क संगठन के कार्य को तेजी प्रदान करने के लिए संगठन द्वारा उत्तरकाशी में भटवाड़ी, छाम तथा क्षेत्रीय कार्यशाला पिथौरागढ़ के लिए राज्य सरकार से भूमि आवंटन का आश्वासन दिया। उन्होंने उत्तरकाशी में निर्माणाधीन बाईपास को पूरा करने के लिए अवशेष धनराशि 10 करोड़ रूपये शीघ्र जारी कराने के निर्देश संबंधित सचिव को दिये। उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए जमा भूमि मुआवजा राशि प्राथमिकता से प्रभावितों को वितरित करने के निर्देश प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को दिये। उन्होंने बदरीनाथ से माधा भैरवघाटी से नीलांग–नागा–जराड़ की निर्माणाधीन सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माणाधीन तवाघाट से घटियाबगड़, घटियाबगड़ से लिपुलेख, मुनस्यारी–बुगडियार–मिलम तथा गुंजी–कुटी–ओलीकोंग की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। ■

राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बने

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ जी ने पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्यब्रत मुखर्जी का इस्तीफा स्वीकार कर श्री राहुल सिन्हा को पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। ■

वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी नहीं रहे

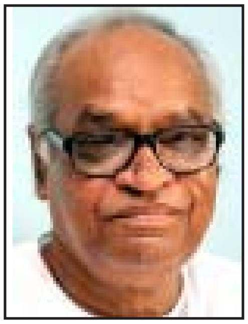

वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता के पूर्व प्रधान संपादक प्रभाष जोशी का 5 नवम्बर, 2009 की रात उनके निवास पर निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह एवं अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। ■

वन्देमातरम् से देवबंदी उलेमाओं को परहेज क्यों?

राष्ट्र-विरोधी फतवा

cYno Hkkbl 'kek

Ok ट के लिए राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने वाले तत्वों के साथ साठ–गांठ करना कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र रहा है। देवबंद में एक बार फिर यह उजागर हो गया जब वंदेमातरम् के खिलाफ फतवा जारी करने वाले जमीयत उलेमा ए हिंद के मंच पर केन्द्रीय गृहमंत्री व कांग्रेसी नेता पी. चिदम्बरम भी पहुंचे और ऐसे राष्ट्रविरोधी .त्य के लिए उलेमाओं को फटकारने की बजाय उनके सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे का विध्वंस साम्प्रदायिक उन्माद के कारण हुआ। यह कांग्रेस ही है जिसके नेताओं ने सत्ता के लिए राष्ट्रद्रोही मनोवृत्ति के सामने सिर झुकाया और मातृभूमि का विभाजन स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, स्वतंत्र भारत में भी इसी लीगी मानसिकता को तुष्टीकरण के द्वारा पाला–पोसा और देश में अलगाववादी व राष्ट्रद्रोही हरकतों को अंजाम देने की खुली छूट दी। इसी का परिणाम है कि आज ये लीगी तत्व भारत में फिर से कई पाकिस्तान बनाने की तैयारी में लगे हैं। यह बेहद शर्मनाक है कि देश का गृहमंत्री उस मंच पर भागीदारी करे जहां से राष्ट्रीय एकता के प्रतीक व देशभक्ति का अलख जगाने वाले राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के विरुद्ध स्वर उभर रहे हों। यह नहीं भूलना चाहिए कि वंदेमातरम् शब्दों की पांत भर नहीं है, यह राष्ट्रीय चेतना की अनुगूंज है जिसने देश की आजादी के लिए देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए असंख्य बलिदानियों को प्राणोत्सर्ग की प्रेरणा दी, कितने ही राष्ट्रभक्त इसी प्रेरणा से हंसते–हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। क्या उलेमा यह भूल गए कि यही वंदेमातरम् बंग–भंग आंदोलन के दौरान हिन्दू–मुस्लिम एकता का सेतु बना था और इसी एकता के आगे अंग्रेजी साम्राज्य ने घुटने टेके व बंगाल का विभाजन रद्द हुआ? अशफाक उल्लाह खां व अब्दुल हमीद जैसे कितने ही देशभक्त मुस्लिमों को इसी जज्बे ने मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्म बलिदान की ओर अग्रसर किया।

दुर्भाग्य से राष्ट्र विरोधी व अलगाववादी तत्व मुस्लिम लीग के रूप में संगठित होकर भारत व हिन्दू–मुस्लिम एकता के दुश्मन बन गए और उन्होंने चुन–चुनकर उन मान–बिन्दुओं को निशाने पर लिया जो राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक थे या हिन्दू मुस्लिम एकता का आधार।

यह बेहद शर्मनाक है कि देश का गृहमंत्री उस मंच पर भागीदारी करे जहां से राष्ट्रीय एकता के प्रतीक व देशभक्ति का अलख जगाने वाले राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के विरुद्ध स्वर उभर रहे हों। यह नहीं भूलना चाहिए कि वंदेमातरम् शब्दों की पांत भर नहीं है, यह राष्ट्रीय चेतना की अनुगूंज है जिसने देश की आजादी के लिए देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए असंख्य बलिदानियों को प्राणोत्सर्ग की प्रेरणा दी, कितने ही राष्ट्रभक्त इसी प्रेरणा से हंसते–हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

यह जहर लीगी नेताओं की रगों में इस कदर फैल गया कि कांग्रेस में रहते हुए वे पार्टी अधिवेशनों के समय वंदेमातरम् के गायन के वक्त मंच छोड़कर जाने लगे। 1937 में जो 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया उसका पहला बिन्दु ही वंदेमातरम् विरोधी था, अगला बिन्दु हिन्दू महापुरुषों का विरोध जताने वाला था। ऐसी नफरत की नींव पर जिस मानसिकता का निर्माण हुआ हो, उससे भारत भक्ति की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन जैसे अंग्रेजों ने इस लीगी नफरत का अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही कांग्रेस ने आजाद भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के द्वारा इन तत्वों की न केवल फलने–फूलने में मदद की, बल्कि हिन्दू हितों व हिन्दू जनभावनाओं को आहत करके इनकी मिजाजपुर्सी की। कांग्रेसी सरकारों की इसी वोट की राजनीति के चलते इन तत्वों को इतनी शह मिली कि देश में करीब 3 करोड़ बंगलादेशी घुसपैठिये बेरोकटोक आ धमके, जो आज न केवल राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन गए बल्कि देश की संप्रभुता व आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। ये जिहादी आतंकवाद के लिए खाद– पानी का काम करते हैं। ये ही तत्व अब पूर्वोत्तर में चालाकी से मुस्लिम बहुल बनाए गए इलाकों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठाने की आंदोलनात्मक तैयारी कर रहे हैं। ऐसी खुफिया रिपोर्टों के मिलने पर देश का गृह मंत्रालय सकते में है। यह बिल्कुल वैसी ही रणनीति है जैसी पाकिस्तान निर्माण के लिए मुस्लिम लीग ने अपनाई थी, तब अंग्रेजी साम्राज्यवाद उसमें सहायक बना था, अब कांग्रेसी सत्ता।

गृहमंत्री के लिए पार्टी हित, वोट की राजनीति क्या देश से बड़ी हो गई, जो वह यह जानते हुए भी कि जिस मंच पर अलगाववादी आवाजें उठ रही हैं, वहां जाकर उनकी पीठ थपथपा आए? गृहमंत्री के यहां से सफाई दी जा रही है कि उनकी उपस्थिति में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, लेकिन यह भी सच है कि उनके सामने एक अन्य प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कहा गया कि वंदेमातरम् का विरोध करने वाला फतवा सही था। यही दारुल

उलूम है जहां 2006 में भी वंदेमातरम् के विरोध में फतवा जारी हुआ था, क्या गृहमंत्री को इतनी भी जानकारी नहीं? जो गृहमंत्री देश के हालात से इस कदर अनभिज्ञ हो, उसे एक क्षण भी इस महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। उधर, जमीयत–उलेमा–ए हिंद ने अपने राष्ट्रविरोधी चरित्र का ही परिचय दिया है। वंदेमातरम् का विरोध राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है।

कोई भी मजहब देशभक्ति का विरोध करना नहीं सिखाता, न इस्लाम ही हुब्बल–वतनी (देशप्रेम) को वर्जित बताता है। फिर फतवे में वंदेमातरम् को इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताए जाने का क्या कारण है? यह राष्ट्रभक्त मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश है, अन्यथा इस समय अकारण और अचानक वंदेमातरम् पर विवाद खड़ा करने की क्या जरूरत है? एक मजहबी सम्मेलन को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल कर वहां से सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू किए जाने व लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने की मांगें उठाए जाने का क्या निहितार्थ है? और केन्द्रीय गृहमंत्री उस मंच पर उपस्थित होते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक व सत्ता स्वार्थों के लिए अलगाववादी तत्वों से साठ–गांठ में लिप्त है और कांग्रेस ने भी वंदेमातरम् के खिलाफ फतवे को स्वीकार कर लिया है।

इसी मंच से गृहमंत्री ने एक नई अवधारणा को जन्म दिया कि इस्लाम विदेशी मजहब नहीं है, जबकि इतिहास साक्षी है कि इस्लाम अरब में जन्मा व आततायी के रूप में पूरे मध्य एशिया में कत्लेआम मचाता हुआ भारत पहुंचा था। यह अलग बात है कि हिन्दुत्व के सर्वसमावेशी चरित्र व सहिष्णु भाव के कारण भारत में हिन्दू राजाओं ने मुस्लिमों को खुलेमन से स्वीकार कर उन्हें मस्जिदें बनाने से लेकर उसकी मजहबी मान्यताओं के विस्तार के लिए पूरा सहयोग दिया। लेकिन कट्टर इस्लाम की हिन्दू विद्वेषी मानसिकता कभी छिपी नहीं रही, लाखों मंदिरों को ध्वस्त किया गया, तलवार के जोर पर असंख्य हिन्दुओं का मतांतरण किया गया। इसी हिन्दू विद्वेषी भारत विरोधी मानसिकता में से लीगी तत्व पनपे और उन्होंने देश का विभाजन कराया। वंदेमातरम् के द्वारा जो राष्ट्रीय भावना बलवती होती है, अब उसे कमजोर करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती।

क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए अब फिर से एक और पाकिस्तान की जमीन तैयार करने की छूट दिया जाना भारत के लिए घोर अनर्थकारी होगा। देवबंद में फिर से यह फतवा जारी किया जाना राष्ट्रीय भावनाओं का अनादर और उन्हें कमजोर करने का षड्यंत्र है। दुनिया के किसी भी देश में देशभक्ति के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है, फिर भारत में यह गफलत क्यों? वंदेमातरम् का विरोध करें और खुद को देशभक्त बताएं, यह विरोधाभास गले उतरने वाला नहीं है। कांग्रेस यह कहकर किसे धोखा दे रही है कि यह संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति न करें? वह वोट की राजनीति के लिए खुद ऐसे अलगाववादी व राष्ट्रविरोधी तत्वों को शह दे रही है जो खुलेआम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने वाले उद्गार वंदेमातरम् का अपमान कर रहे हैं और गृहमंत्री जाकर उनकी पीठ थपथपाते हैं। यह अक्षम्य है, देश के स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति व देशहित के साथ ऐसा कोई समझौता पूरी तरह अस्वीकार्य है। देश ने इसकी कीमत पहले भी चुकाई है, अब और नहीं। भारत का राष्ट्रभक्त मुस्लिम समाज भी ऐसे फतवों के विरुद्ध है, यह इसकी प्रतिक्रिया में सामने आ चुका है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्रभक्त का मंत्र है वंदेमातरम्। ■

पृष्ठ 5 का शेष

लाइसेंस से 7000 करोड़ रूपए से अधिक का नुकसान हुआ। इन स्पेक्ट्रमों से कुल मिलाकर इन 9 लाइसेंसों में यह नुकसान 60,000 करोड़ रूपए से अधिक बैठता है।

यह नुकसान तो और भी कई गुना बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि बाजार में कौड़ियों के दाम इन अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के दाम उन 3–जी स्पेक्ट्रम के मूल्य से भी बढ़ जाते हैं, जब अब सरकार इनकी नीलामी करने की बात सोच रही है। यदि ईओजीएम के निर्णय के अनुसार 3–जी स्पेक्ट्रम की होती है तो फिर यही सिद्धांत 2–जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के समय क्यों नहीं लिया गया?

भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा मानसून सत्र में संसद में उठाया था। भाजपा ने मांग की थी कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के अधीन किसी भी सरकारी अधिकारी (पब्लिक सर्वेंट) को आपराधिक कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह भ्रष्ट तरीके या गैर कानूनी ढंग से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी बहुमूल्य वस्तु या आर्थिक लाभ के लिए धन प्राप्त करता है। इस प्रावधान से उसे 7 वर्ष की कैद हो सकती है। स्पष्ट है कि इस मामले में स्वयं मंत्री महोदय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्री ए. राजा इस अपराध के लिए मुख्य रूप से दोषी हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने मंत्री महोदय को निर्दोष ठहराने के बारे में टिप्पणी की है जबकि अभी जांच का काम चल ही रहा है। यह ऐसा अवसर नहीं था कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने नियंत्रण में चल रही जांच एजेंसी को इस प्रकार का सिगनल देते। सच यह है कि यदि मंत्री महोदय यूपीए के गठबंधन के सहयोगी हैं तो उन पर पर्दा डालने का कोई आधार नहीं बनता है। दूरसंचार विभाग की इस काली करतूत से देश को एक बहुत बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ा है। गठबंधन की राजनीति की मजबूरी किसी भी ईमानदारी से जांच करने के आड़े नहीं आनी चाहिए। औचित्य यही है कि जब तक जांच का काम चल रहा है, मंत्री महोदय को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्रालय में उनके बने रहने से स्वतंत्र और ईमानदारी से जांच करने के काम में बाधा आएगी। पूरा देश इस जांच पर कड़ी निगाह रखे है। अच्छा होगा कि जांच का परिणाम सिविल अधिकारियों और मंत्री को निर्दोष ठहराने की परिणति न बन जाए। मंत्री महोदय प्रमुख अभियुक्त है और सिविल अधिकारीगण तो केवल उनके हुकुम की तामील कर रहे थे। ■

एक बार फिर कांग्रेसी अलगाववाद

e|[rkj vCckl udoh

fdसी भी कार्यक्रम की शुरूआत वंदेमातरम् से हाती है। सवाल यह नहीं कि हर कार्यक्रम की शुरूआत वंदेमातरम् के साथ की जाए या नहीं। वैसे भी राष्ट्रीय गीत गाने के बारे में किसी ने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की है। यह खुद की इच्छा पर है कि इसे गाया जाए या न गाया जाए। लेकिन, यहां सवाल उससे भी बड़ा है। क्या किसी कार्यक्रम में प्रस्ताव पारित हो कि वंदेमातरम् को न गाया जाये। देवबंद के कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत का यह घोर अपमान हुआ।

वह भी तब जब उसमें देश के गृहमंत्री पी चिदंबरम भी मौजूद थे। वह गृहमंत्री, जिन पर देश के शांति व सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं के साये में देश को बांटने का काम होता है। और वे चुप रहे। फतवे का विरोध तक नहीं किया। एक शब्द तक नहीं बोले। उनकी उपस्थिति और उनकी चुप्पी ने परोक्ष रूप से इस फतवे को वैधानिकता प्रदान कर दी।

बाद में गृहमंत्री यह कहते हुए अपनी सफाई देते हैं कि वह इस तरह के प्रस्ताव से अनभिज्ञ थे। फिर सवाल यह कि आखिरकार वे कैसे इतने बड़े मामले से अनभिज्ञ रह सकते हैं। उनके पास तो देश का पूरा खुफिया अमला है। साथ ही जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाते हैं। उस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में खुफिया विभाग पहले से पूरी छानबीन करता है। फिर वंदेमातरम् के खिलाफ फतवे के समर्थन की खबरें तो उसी दिन सवेरे अखबारों में छपी थी।

इस मामले पर चिदंबरम को कांग्रेस का समर्थन बड़ी बात नहीं है। असल में कांग्रेस ने हमेशा से इस तरह के मामलों पर लचीला रवैया अपनाया तथा इससे देश में आतंकवाद–अलगाववाद को बढ़ावा दिया। साथ ही कांग्रेस की नीति भी रही है कि देश को धर्म के आधार पर बांटो और राज करो। हिंदू–मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाओ, डराओ, धमकाओ और मुस्लिमों को वोट हासिल कर सत्ता करो। लेकिन इसका खामियाजा मुस्लिमों को भुगतना पड़ा। वह आज हर क्षेत्र में पिछड़े हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आंखे खोलने वाली है। जनता को समझना होगा कि उनके पिछड़ेपन का दोषी कौन है, जिसने देश में कई दशकों तक राज किया और कर रही है। यानि कांग्रेस।

> ***आजादी की जंग में राष्ट्रगीत हिंदू–मुस्लिम सभी के सीनों में समान रूप से धड़कता था। उस समय भी खाई चौड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन नाकाम रहे। आजादी के बाद भी ऐसे प्रयासों में कमी नहीं आई है। बार–बार राष्ट्रगीत का विवाद खड़ाकर यही करने का प्रयास होता रहा है। लेकिन चंद लोगों का यह प्रयास कभी कामयाब नहीं हुआ। अधिकांश मुस्लिम अमन पसंद है। और उनके सीने में भी वंदेमातरम् हिंदू के समान धड़कता है। यह कामयाब नहीं हुआ तो कोई और विवाद खड़ा कर दिया। सबसे चिंतनीय बात की इसे अब सरेआम सरकार का संरक्षण मिलने लगा है।***

आजादी की जंग में राष्ट्रगीत हिंदू–मुस्लिम सभी के सीनों में समान रूप से धड़कता था। उस समय भी खाई चौड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन नाकाम रहे। आजादी के बाद भी ऐसे प्रयासों में कमी नहीं आई है। बार–बार राष्ट्रगीत का विवाद खड़ाकर यही करने का प्रयास होता रहा है। लेकिन चंद लोगों का यह प्रयास कभी कामयाब नहीं हुआ। अधिकांश मुस्लिम अमन पसंद है। और उनके सीने में भी वंदेमातरम् हिंदू के समान धड़कता है। यह कामयाब नहीं हुआ तो कोई और विवाद खड़ा कर दिया। सबसे चिंतनीय बात की इसे अब सरेआम सरकार का संरक्षण मिलने लगा है।

जमीयत उलेमा हिंद के उस कार्यक्रम में महिला आरक्षण पर समेत अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए। जिनपर कुछ को ऐतरजा हो सकता है। उस पर यही कहा जा सकता है कि कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इस पर नहीं कि जिस मिट्टी में पले–बढ़े, जिस भारत मां ने पाला–पोसा, जिसने सीने पर खड़े होकर हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, उसी का अनादर करें। यह सोचकर शर्म महसूस हो रही है। यह अलगाववादी मानसिकता का परिचायक है। और जितना तीखा विरोध हो सके। इसका करना चाहिए। वंदेमातरम् का विरोध समझ से परे है।

मुस्लिमों को यदि आगे बढ़ना है तो इस तरह की ओछी हरकतों से बाज आए। कांग्रेस की नीति शुरू से ही तुष्ट करने की नीति रही है। चिदंबरम को कठोर कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं करके कांग्रेस की जो असली नीति है उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ■

जनता का समर्थन भाजपा के साथ : करुणा शुक्ला

''झारखंड की जनता एक स्थायी सरकार और कुशल नेतृत्व चाहती है, जो उसे भाजपा में ही दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से इस चुनाव में हमें मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होगा।'' यह कहना है भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड प्रदेश भाजपा प्रभारी व पूर्व सांसद श्रीमती करूणा शुक्ला का। झारखंड विधानसभा चुनाव के निमित्त 'कमल संदेश' से हुयी भेंटवार्ता में श्रीमती शुक्ला ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की। हम यहां इस भेंटवार्ता के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं:–

प्र. झारखण्ड विधानसभा का चुनाव हो रहा है इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं?

उ. देखिए इस चुनाव में मुद्दे स्पष्ट हैं झारखण्ड की जनता गत तीन वर्ष से अस्थिर शासन व्यवस्था के कारण से त्रस्त है। इन तीन वर्षों में इस प्रदेश का विकास मानो थम सा गया है। फिर चाहे कांग्रेस समर्थित एक निर्दलीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो या झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का शासनकाल। इस प्रदेश की जनता के साथ घोर अन्याय हुआ है। इन तीन वर्षों में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी गई हैं। आज आप जो कुछ देख रहे हैं सुन रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और लालूप्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी द्वारा समर्थित एक निर्दलीय मुख्यमंत्री की सरकार के कारनामे सबके सामने हैं। झारखण्ड की जनता का और संसाधनों का भरपूर शोषण किया गया है जिससे झारखण्ड की जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। वहीं भाजपा की श्री अर्जुन मुण्डा के नेतृत्व वाली सरकार को जिस तरह षड्यंत्र करके गिराया गया और उसके बाद झारखण्ड के राजनीतिक परिदृश्य में जो अस्थिरता देखने को मिली उससे भी यहां की जनता निजात पाना चाहती है। इसलिए स्थाई सरकार का भी एक मुद्दा इस चुनाव में प्रभावी होगा। इसके अलावा बिजली, सड़क, पानी आदि बुनियादी आवश्यकताओं की कमी भी चुनाव में मुद्दे होंगे।

इस चुनाव में एनडीए मजबूती के साथ चुनाव समर में उतरी है और विकास का नारा लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आदिवासी बाहुल्य झारखण्ड प्रदेश जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है यहां के हर गरीब जनता को अनाज मिले उसके घर में चूल्हा जले। पूरे प्रदेश में विकास का प्रकाश पहुंचे।

प्र. क्या इस चुनाव में महंगाई भी मुददा होगा?

उ. देखिए पूरे देश में जिस तरह से महंगाई बेलगाम बढ़ रही है। और केन्द्र की यूपीए सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, इसे यह भी कह सकते हैं कि केन्द्र की सरकार इस महंगाई को रोक पाने में असफल साबित हुई है। इससे यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। महंगाई तो आज पूरे देश में मुद्दा है। झारखण्ड की जनता तो इससे तबाह हो ही रही है। आज इस महंगाई ने बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया है। दूध छीन लिया है। गरीबों की हालत तो बद से बदतर है। इस महंगाई में तो नमक और रोटी भी जुटा पाना मुहाल हो गया है। वैसे तो महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है। पर इसका प्रभाव सर्वाधिक गरीबों पर पड़ता है। रोजगार नहीं हैं। कमाई नहीं है। रोटी के लाले हैं। ऊपर से यह बेलगाम बढ़ती महंगाई। मुझे तो कई बार समझ नहीं आता कि आखिर यह केन्द्र की कांग्रेस समर्थित यूपीए सरकार चाहती क्या है?

प्र. केन्द्र में जब एनडीए की सरकार थी तब अटलजी के विशेष प्रयास से तीन नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड व झारखण्ड का गठन हुआ। वर्तमान में उत्तराखण्ड व छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। इन राज्यों में जिस तरह से भाजपा की सरकार चल रही है, क्या इसका प्रभाव भी इस चुनाव में पड़ेगा?

उ. आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह बहुत अच्छी तुलना भी है। आज उत्तराखण्ड में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में तो हम दुबारा चुनकर आए हैं। मेरा सम्बंध छत्तीसगढ़ से बहुत निकट का रहा है। आज उत्तराखण्ड में माननीय निशंक जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वह विकास के नए आयाम को तय कर रही है। जनता में खुशहाली है। विकास के कार्य द्रुतगति से चल रहे हैं। तमाम उपलब्धियों से भरी हुई भाजपा की सरकार जनहित में कार्य कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है। यह नवनिर्मित राज्य आज पूरे देश में अव्वल राज्य है। कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। जो विकास के कार्य आदिवासी बाहुल्य राज्य

छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं उसे आज सारा देश सराह रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्षेत्र की जनता ने डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार के विकास कार्यों को देखकर उसे दोबारा भारी बहुमत से जिता कर लाई है। झारखण्ड छत्तीसगढ़ से सटा हुआ पड़ोसी राज्य है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों एवं भाजपा की नीतियों का प्रभाव झारखण्ड की जनता महसूस करती है। मैं समझती हूं कि उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और झारखण्ड की जनता इस बार भाजपा को भारी बहुमत से जिता कर सरकार बनाने का अवसर देगी।

प्र. भाजपा ने इस चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रस्तुत नहीं किया है। भाजपा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी?

उ. देखिए, जब हमने छत्तीसगढ़ का भी पहला चुनाव लड़ा था तब भी हमने किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है, हम झारखण्ड में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व और विकास का संकल्प लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। हम जनता में सुख समृद्धि और शांति लाने के लिए संकल्पित हैं। विकास के बल पर हम झारखण्ड की जनता में विश्वास कायम करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमारा उद्देश्य है हर गरीब को अनाज मिले, हर घर में चूल्हा जले और विकास की गंगा पूरे प्रदेश में प्रवाहित हो।

प्र. इस चुनाव में विभिन्न राष्ट्रीय दलों के अलावा क्षेत्रीय दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से एक झारखण्ड जनहित दल जिसका नेतृत्व बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। वे भी चुनाव मैदान में हैं क्योंकि वे पूर्व में भाजपा से सम्बंधित रहे हैं उसे भाजपा किस रूप में ले रही हैं?

उ. देखिए, बाबूलाल मरांडी की कलई खुल गई है। जिस तरह से कुर्सी की चाहत के लिए मरांडी जी ने कांग्रेस के साथ समझौता किया है और चुनाव में उतरे हैं, उसको झारखण्ड की जनता पहचान चुकी है। यह वही कांग्रेस है जिसके समर्थन पर एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन बैठा और पूरे प्रदेश का शोषण करता रहा तथा आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गया। फिर इसी कांग्रेस के समर्थन से इस प्रदेश में शीबू सोरेन मुख्यमंत्री बने उनके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रदेश क्या पूरा देश उनके घोटालो व कारनामों से परिचित है। झारखण्ड की जनता ने एक कार्यकारी मुख्यमंत्री जिसकी नेतृत्व में प्रदेश की सरकार चल रही है उसे हरा कर पूरे देश को यह संदेश दिया कि झारखण्ड की जनता कांग्रेस व लालू के समर्थन वाली भ्रष्टाचारी सरकार से निजात पाना चाहती है। फिर कांग्रेस ने इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जनता इसके विरूद्ध भी सड़क में उतर आयी। आज उसी कांग्रेस से मरांडी जी का गठबंधन एक अवसरवादी गठबंधन है। क्षेत्र की जनता एक स्थाई सरकार और कुशल नेतृत्व चाहती है। जो उसे भाजपा में ही दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से इस चुनाव में हमें झारखण्ड की जनता का मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होगा और झारखण्ड में भाजपा की सरकार बनेगी। ■

कोड़ा और कानून के बीच राजनीति न आए

vk म जनता की यह शिकायत रही है कि अपराधी होने के बावजूद महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति को सजा नहीं मिलती। इस छवि को तोड़ने का वक्त आ गया है।

राजनीतिक भ्रष्टाचार का रूप भयावह होने की हद को पार कर गया है, तभी तो अब हजारों करोड़ के गबन से भी चौंकते नहीं। बोफोर्स घोटाले में घूस की राशि सिर्फ 64 करोड़ थी, पर आरोप भर लगने से केंद्र की सरकार गिर गई थी। जांच एजेंसियों की मानें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा चार हजार करोड़ से ज्यादा की सरकारी रकम गटक गए। इस खबर पर कोई हंगामा नहीं बरपा। जब जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ के लिए घेरा डालने लगीं तो कोड़ा अस्पताल में भर्ती हो गए।

लालू प्रसाद के दुलारे निर्दलीय विधायक कोड़ा ने 'गुरु गुड़ चेला चीनी' की कहावत को नया अर्थ दे दिया है। लालू के जमाने में हुआ चारा घोटाला उस वक्त भारत का सबसे बड़ा घोटाला बन गया था। इस क्रम में लालू कई बार जेल यात्रा कर चुके हैं। अब लगता है कोड़ा द्वारा अंजाम दिया गया गबन देश का सबसे बड़ा गबन हो सकता है। कोड़ा की जेल यात्रा अब शुरू होगी, पर राजनीतिक भ्रष्टाचार की शृंखला का यह अंत नहीं है। हालांकि जनता को इससे यह संतोष मिलेगा कि कार्रवाई हो रही है।

झारखंड में माओवादियों की पकड़ इसीलिए मजबूत हुई क्योंकि वहां का सरकारी तंत्र आदिवासी कल्याण और विकास के पैसे का गबन करता रहा। कोड़ा की सरकार कैसे चल रही थी, यह जगजाहिर था। यहां तक कि कोड़ा ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने समर्थन खरीदा था। केंद्र सरकार उनके कुकृत्यों से अवगत न हो, ऐसा संभव नहीं है।

सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए देश के भीतर और बाहर व्यक्तिगत रूप से ले जाने वालों की खबर भी केंद्रीय एजेंसियों को थी, पर तब कोड़ा करीबी थे और राजनीतिक मोहरे भी। झारखंड में सरकार जाने के बाद कोड़ा पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अब चुनाव आ गए हैं और कोड़ा इसे राजनीतिक द्वेष से उपजा षड्यंत्र बताएंगे, पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे स्पष्ट अंत तक पहुंचना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले सीबीआई को बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। सीबीआई ने एक बड़ी मछली को फांसकर दिखाया है। अब जरूरत है कि केंद्र सीबीआई को आगे बढ़ने दे। देश की जनता की यह शिकायत आम रही है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति को सजा नहीं मिलती, चाहे वह कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो।

इस छवि को तोड़ने के लिए अब वक्त आ गया है कि कुछ उदाहरण स्थापित किए जाएं। कोड़ा अगर करोड़ों के वारे–न्यारे करने के दोषी हैं तो उनके और कानून के बीच राजनीति नहीं आनी चाहिए। ■

कांग्रेस की देर से चुनाव कराने का षड्यंत्र उसे ले डूबेगा : रघुबर दास

झारखण्ड में राज्य विधान सभा के चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। भाजपा ने अपने विरोधियों का सामना करने के लिए कमर कस ली है। पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर सुनिश्चित करने में लगे हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सत्ता में लौटे। झारखण्ड के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री रघुबर दास ने 'कमल संदेश' के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की, जिसके प्रमुख अंश नीचे प्रस्तुत हैः–

⏭ झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस कारण राज्य के विकास में बाधा पड़ी है?

राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत झारखण्ड की हालत बदतर हुई है। उम्मीद तो यह थी कि राष्ट्रपति शासन राज्य में बेहतर शासन का प्रदर्शन करेगा, परन्तु यहां एकदम विपरीत ही हुआ। इसमें सबसे अधिक क्षति कानून और व्यवस्था की हुई। विकास केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। लोगों को कहीं भी विकास देखने को नहीं मिला। कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों ने राज्यपाल के पद को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया। सीबीआई के छापों ने ही तत्कालीन राज्यपाल श्री सिब्ती रिजवी के निजी सचिव और ओएसडी के कथित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके रख दिया है और इससे करोड़ों रुपयों की बेनामी सम्पत्ति का पता चलता है। विकास की उपेक्षा हुई और भ्रष्टाचार पनपता रहा। वहां जो भी सरकारें आती रही, उन्होंने दिखा दिया कांग्रेस ने अवैध साधनों से लोगों को खूब लूटा ही लूटा।

⏭ राज्य में यूपीए ने चुनाव कराने में देरी क्यों की?

चुनाव देरी से कराने का कारण यही था कि कांग्रेस कठपुतली सरकार के जरिए अपने राजनैतिक तथा चुनावी एजेण्डे से स्वार्थपूर्ति करना चाहती थी। परन्तु तरह–तरह के लालच और धमकियों से भी कांग्रेस अपनी साजिश और हेराफेरी करके भी सरकार बनाने में असफल रही। अंत में उसके पास कोई विकल्प बचा ही नहीं और इसलिए चुनाव कराने ही पड़े। इसी दौरान झारखण्ड के गरीब लोगों को ही बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ा है।

⏭ चुनाव देर से कराने में किसको लाभ हो सकता है?

निश्चित ही कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस ने चुनाव कराने में देरी करके राजनैतिक लाभ उठाया क्योंकि उसे पता था कि जब कभी भी चुनाव होंगे तो लोग उसे सत्ता से बाहर कर ही देंगे और भाजपा सत्ता में आ जाएगी। इस वर्ष मई में लोकसभा के चुनाव परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं। यही कारण है कि चुनाव कराने में जितनी देरी हो सकी, वह उसने की। अब कांग्रेस पर यही सारी चालबाजियां उलटी पड़ गई है और भाजपा को इससे लाभ होगा।

जब शिबू सोरेन तमार विधान सभा उपचुनाव में हार गए थे और भाजपा सहित कोई भी पार्टी उस समय सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी तभी कांग्रेस को तुरंत विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराने चाहिए थे ताकि जनता अपनी मर्जी की सरकार चुन सके। यदि कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो आज स्थिति इतनी न बिगड़ती। कांग्रेस ने श्री मधु कोड़ा को संरक्षण दिया और इसी कारण आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में आज तक सबसे बदतर किस्म का 4800 करोड़ रूपए से भी अधिक का घोटाला देखने को मिला। इस घोटाले से झारखण्ड का सिर पूरे देश और विश्व में शर्म से झुक कर रह गया है।

⏭ पूर्व राज्यपाल के आचरण पर उंगलियां उठी हैं। अब क्या स्थिति है?

तत्कालीन राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि जो कुछ भी हुआ सभी कुछ राजभवन की नाक तले हुआ। उनका तबादला असम में कर दिया गया। भाजपा की मांग है कि उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनकी भी सम्पत्ति की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया जाए।

⏭ विधान सभा चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे?

विधान सभा चुनावों में बहुत से मुद्दे हैं, परन्तु प्रमुख रूप से बेलगाम भ्रष्टाचार, विकास की अनदेखी, आम आदमी के जीवन और सम्पत्ति की असुरक्षा और इससे भी अधिक

शेष पृष्ठ 19 पर

जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है

&loknnkrk }kjk

झारखंड में विधानसभा चुनाव–प्रचार जोरों पर है। राज्य की तीसरी विधानसभा के लिए चुनाव पांच चरणों में होंगे। पहला चरण 25 नवंबर को और आखिरी 18 दिसंबर को संपन्न होगा। मतगणना 23 दिसंबर को की जाएगी। 1,80,27,476 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 9 एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं। इस साल 19 जनवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है जिसकी समयावधि अगले साल 18 जनवरी को समाप्त हो रही है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से 9 मार्च 2010 को समाप्त होनेवाला है।

झारखंड में तीन प्रमुख दल हैं भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। इसके अलावा जदयू, राजद, यूजीडीपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, भाकपा माले और एनसीपी भी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और जदयू विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने पर राजी हो गए हैं। समझौते के मुताबिक जदयू अब 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गत लोकसभा चुनाव में भाजपा को 14 में से 8 सीटें मिली थी। इसी के चलते भाजपा के हौसले बुलंद हैं। बाबूलाल मरांडी 2006 में भाजपा से अलग होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

विगत विधानसभा में दलगत स्थिति

विधानसभा सदस्य संख्या–		82
भाजपा	–	30
जदयू	–	06
एनसीपी	–	01
मनोनीत	–	01
झामुमो	–	17
कांग्रेस	–	09
राजद	–	07
फॉरवर्ड ब्लॉक	–	02
भाकपा माले	–	01
यूजीडीपी	–	02
निर्दलीय	–	06

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा 2 मार्च, 2005 को अस्तित्व में आयी थी। इसकी दूसरी विधानसभा के साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में राज्य ने चार मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति शासन का दौर भी देखा। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली जबकि भाजपा के अर्जुन मुंडा भी राज्य में मुख्यमंत्री बने।

आज झारखण्ड विकास के निचले पायदान पर खड़ा है तथा पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दर्ज नहीं करा पाया है। भाजपा शासन में जो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी पिछले तीन वर्षों में सत्ता की बंदरबाट एवं प्रदेश के संसाधनों में लूट–पाट के कारण थम सी गई है। विकास के मानण्डों पर अपनी छाप छोड़ने के स्थान पर झारखण्ड अब भ्रष्टाचार, सिद्धांतहीन राजनीति, लूट–पाट एवं नक्सलवाद के लिए देश में जाना जा रहा है।

देश के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरकार के अल्पमत में आने के बाद इस साल जनवरी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस अवधि में विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर दो विधायक इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम पहुंचे।

15 नवम्बर 2009 को झारखण्ड राज्य अपने नौ वर्ष पूरे कर लेगी। वर्षों के सौतेले व्यवहार, भेदभाव एवं लगातार सरकारों द्वारा नजरअंदाज किये जाने के कारण अलग झारखण्ड राज्य की मांग ने जोर पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने ''वनांचल आंदोलन'' के नाम से अलग राज्य की मांग को बल दिया तथा पूरी झारखण्ड की जनता को इस मांग के समर्थन में एकजुट किया। इस आंदोलन के फलस्वरूप केन्द्र की भाजपा नीत राजग सरकार ने 15 नवंबर 2000 को प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अलग राज्य का गठन किया।

आज झारखण्ड विकास के निचले पायदान पर खड़ा है तथा पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दर्ज नहीं करा पाया है। भाजपा शासन में जो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी पिछले तीन वर्षों में सत्ता की बंदरबाट एवं प्रदेश के संसाधनों में लूट–पाट के कारण थम सी गई है। विकास के मानण्डों पर अपनी छाप छोड़ने के स्थान पर झारखण्ड अब भ्रष्टाचार, सिद्धांतहीन राजनीति, लूट–पाट एवं नक्सलवाद के लिए देश में जाना जा रहा है।

फरवरी 2005 में विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी परन्तु केन्द्र के कांग्रेसनीत संप्रग गठबंधन की सरकार के निर्देश पर राज्यपाल ने शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। अलोकतांत्रिक ढंग से मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन का पता था कि उनके पास सदन में बहुमत नहीं था। अतः हार को सामने देख उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 12 मार्च 2005 को अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने शपथ लिया। यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हुए तथा वह बराबर सरकार को अस्थिर कर गिराने के ताक में लगे रहे। सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं जनता के प्रति जवाबदेही को ताक पर रखते हुए कांग्रेस–झामुमो के समर्थन से एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 18 सितम्बर 2006 से 26 अगस्त 2008 तक मुख्यमंत्री के रूप में मधु कोड़ा तथा इनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कांग्रेस–झामुमो के साथ मिलकर प्रदेश को जमकर लूटा तथा झारखण्ड के विकास को रोक दिया। शिबू सोरेन जो हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट रहे थे, कोर्ट द्वारा बरी होते ही मुख्यमंत्री बनने पर अड़ गये। उनके जिद के सामने कांग्रेस ने आत्मसमर्पण करते हुए उन्हें फिर से 27 अगस्त 2008 को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिबू

सोरेन के सिद्धांतहीन राजनीति एवं भ्रष्ट शासन को जनता ने करारा जवाब उन्हें विधायक के चुनाव में हराकर दिया।

शायद ही कभी स्वतंत्र भारत में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक का चुनाव हारा हो। यह देश की राजनीति में एक बड़ी घटना है। परन्तु हार के बाद भी बहुत दिनों तक शिबू सोरेन बेशर्मी से मुख्यमंत्री बने रहे। अंततः 13 जनवरी 2009 को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रदेश की जनता के हितों को ताक पर रखकर यह सारा खेल भाजपा को सत्ता से बाहर रखने तथा सत्ता की बंदरबांट कर प्रदेश को लूटने का था। इससे कांग्रेस–झामुमो को अलोकतांत्रिक चेहरा तो जनता के सामने उजागर हुआ ही साथ में इनकी सिद्धांतहीन, अनैतिक राजनीति पर से भी परदा उठ गया।

झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में दोषी पाया है। ऐसी पहली घटना है जबकि कोई पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे आरोपों के तहत दोषी पाया गया हो। मधुकोड़ा के साथ–साथ इनके मंत्रिमंडलीय के अन्य सदस्य एनोस एक्का तथा हरिनारायण राय भी जालसाजी, धोखाधड़ी, गबन तथा विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के दोषी पाये गये हैं। जांच में पाया गया है कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अकूत धन अर्जित किया तथा हांग–कांग, थाईलण्ड, लाइबेरिया जैसे देशों में खान कम्पनियों, ठेकों तथा चल–अचल सम्पत्तियों को खरीद रखा है। इसी तरह शिबू सोरेन हत्या के जुर्म में जेल में बंद रहे तथा बाद में विवादास्पद तरीके से छूटे। उनपर अभी भी अनेक मामले लम्बित हैं। परन्तु कांग्रेसनीत संप्रग सरकार को इन्हें मुख्यमंत्री स्वीकारने में तनिक भी देर नहीं हुई। भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया।

राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है तथा अपेक्षा की जाती है कि राज्यपाल दलगत राजनीति से ऊपर रह निष्पक्षता से अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। परन्तु कांग्रेस राज्यपाल के पद का सत्ता के लिए दुरूपयोग करने के लिए दशकों से जानी जाती रही है। सत्ता के बंदरबांट पर कांग्रेस और सोनिया गांधी कभी शिबू सोरेन को तो कभी मधु कोड़ा को राज्यपाल के पद का दुरूपयोग कर मुख्यमंत्री बनाते रहे। यहां तक की समाचारपत्रों के अनुसार झारखण्ड के पूर्व राज्यपाल सिब्तेरजी स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये। राज्यपाल पद का ऐसा दुरूपयोग एवं पद की गरिमा इस प्रकार से शायद ही कभी गिरी हो।

हाल में पुलिस इंस्पेक्टर, फ्रांसिस इंदिवर की निर्मम हत्या से नक्सल–माओ उग्रवाद प्रदेश में बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006 में 124, 2007 में 157, 2008 में 2007 लोग नक्सल–माओ उग्रवाद में अपनी जान गंवा चुके है। वर्ष 2009 में अब तक 150 लोग नक्सल उग्रवाद के कारण मारे जा चुके हैं। पूरे राज्य में नक्सल–माओवाद समानान्तर सरकार चला जनता को लूट रहे हैं और विरोध करने वालों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। नक्सलियों ने प्रदेश के 22 में से 16 जिलो को "गुरिल्ला जोन" में परिवर्तित कर दिया है। ये जिले हैं– गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रांची, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, सराईकेला–खरसावां, कोडरमा। हाल में ये दुमका, देवघर, जामताड़ा और गोड़ा तक में फैल चुके हैं। नक्सल–माओ उग्रवाद के कारण अब तक लगभग 1350 लोग मारे जा चुके हैं जिनमें सांसद सुनील महतो तथा विधायक रमेश सिंह मुंडा भी शामिल हैं। प्रदेश में जनविरोधी–अलोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा भ्रष्टाचार एवं लूट–पाट के कारण भी नक्सलवाद–माओवाद का विस्तार तेजी से हुआ है।

शिबू सोरेन हत्या के जुर्म में जेल में बंद रहे तथा बाद में विवादास्पद तरीके से छूटे। उनपर अभी भी अनेक मामले लम्बित हैं। परन्तु कांग्रेसनीत संप्रग सरकार को इन्हें मुख्यमंत्री स्वीकारने में तनिक भी देर नहीं हुई। भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया गया।

झारखण्ड की गणना देश के अत्यधिक पिछड़े राज्यों में होती है जहां की जनता गरीबी–भूखमरी की चपेट में है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन द्वारा गठित एन.सी. सक्सेना समिति के अनुसार झारखण्ड की 82 प्रतिशत जनता गरीब है। केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य से 42 प्रतिशत जनता गरीब है। ये दोनों आंकड़े राष्ट्रीय आंकड़ों से कहीं अधिक हैं। भ्रष्टाचार के कारण खाते–पीते घर के लोग बीपीएल कार्ड पा जाते हैं जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को यह कार्ड मिल नहीं रहा। ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2008 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों ने बीपीएल कार्ड के लिए 16 करोड़ रूपये केवल रिश्वत में दिया। इससे झारखण्ड में फैले भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है– यहां तक की गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को भी अपने अधिकार के लिए रिश्वत देना पड़ रहा है।

झारखण्ड प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एवं ऐसा राज्य है जहां की जनता अत्यंत गरीब है। यह एक विचित्र विडम्बना है जिसका गंभीरता से अध्ययन होना चाहिए। इस प्रदेश में देश के खनिज सम्पदा का 40 प्रतिशत उपलब्ध है। यह प्रदेश देश के कुल कोयला उत्पाद का 40 प्रतिशत तथा लौह उत्पाद का 20 प्रतिशत उत्पादन करता है। झारखण्ड में 3.7 बिलियन टन लौह अयस्क का भण्डार उपलब्ध है। एक अनुमान के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों से भी अधिक खनिज झारखण्ड में उपलब्ध है। खनिज सम्पदा के अलावा खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, जड़ी–बूटी आदि क्षेत्र में भी प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। लम्बित पड़ी परियोजनाओं को ही यदि कार्यान्वित किया जाय तो प्रदेश में एक लाख नये रोजगार तत्काल पैदा किए जा सकते हैं। यह एक विडम्बना ही है कि झारखण्ड बिहार से अलग कर बनाया गया था– अब जबकि बिहार प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है झारखण्ड पिछड़ रहा है। इस वर्ष बिहार का विकास दर झारखण्ड से अधिक रहा है।

झारखंड के मतदाताओं के समक्ष प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का सुअवसर आया है और इसे साकार करने के लिए मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक ताकत का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। ■

लूट के लोकतांत्रिक तरीके

jktho lpku

eधु कोड़ा दो हजार करोड़ रुपये की काली कमाई करने में सक्षम रहे तो इसके लिए उन्हें और उनके साथियों को केंद्र सरकार को खास तौर पर साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि बगैर उसके सहयोग के वह 23 माह में करीब 24 खदानों को पट्टे पर देने का काम मनमाने तरीके से नहीं कर सकते थे। यह रहस्यमय है कि जब कोड़ा कोयला और लौह खदानों को पट्टे पर देने की दनादन सिफारिश कर रहे थे तब केंद्र सरकार उन पर आंख मूंदकर मोहर क्यों लगा रही थी। क्या इसलिए कि कोड़ा की काली कमाई का एक हिस्सा कांग्रेसजनों की जेब में भी पहुंच रहा था। कांग्रेसजन ऐसे किसी आरोप से इनकार करेंगे, लेकिन यह मानने के पर्याप्त परिस्थितिजन्य कारण हैं कि निर्दलीय होते हुए भी कोड़ा 23 महीने तक सिर्फ इसलिए सरकार चलाते रहे, क्योंकि उनकी काली कमाई से उन्हें समर्थन देने वाले राजनीतिक दल—कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्तिमोर्चा भी लाभान्वित हो रहे थे। कोड़ा ने एक बार कहा भी था कि पैसे का खेल नहीं होता तो वह एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे रह सकते थे।

> ***कहते हैं कि कोड़ा खदानों का पट्टा देने के एवज में 150—200 करोड़ वसूलते थे। चूंकि कोड़ा दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति इकट्ठा करने में सफल रहे इसलिए यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि देशी—विदेशी कंपनियों ने उन्हें खुशी—खुशी भारी भरकम रिश्वत दी।***

स्पष्ट है कि कोड़ा की ओर से की गई लूट—खसोट के लिए अकेले वही दोषी नहीं हैं, लगता यही है कि मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत की कोई भी सरकारी एजेंसी इसके सबूत नहीं जुटा सकती। यह भी समय बताएगा कि कोड़ा को उनके किए की सजा मिल पाती है या नहीं, क्योंकि वह एक राजनेता हैं और अब तक का अनुभव यही बताता है कि भारत में राजनेताओं के खिलाफ जांच—पड़ताल तो होती है और वे अदालतों के चक्कर भी काटते हैं, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिलती। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यदि कोड़ा अपने दो—तीन साथियों समेत जीत जाते हैं और त्रिशंकु सदन की स्थिति बनती है तो वह सरकार गठित करने वाले दल के लिए फिर से आदरणीय—प्रातः स्मरणीय बन सकते हैं।

> ***देश के नीति—नियंताओं को यह देखकर चुल्लू भर पानी की तलाश करनी चाहिए कि कोई दो हजार करोड़ के वारे—न्यारे कर रहा है और कोई 60 हजार करोड़ के। एक ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग महज 30—40 रुपये प्रतिदिन पर गुजर—बसर करने के लिए विवश हैं वहां हजारों करोड़ की हेराफेरी एक झटके में हो रही है और सत्ता के शीर्ष केंद्र में एक पत्ता तक नहीं खड़कता।***

यदि झारखंड में किसी तरह कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो जाए और उसे मधु कोड़ा के भीतरी या बाहरी समर्थन की जरूरत पड़े तो आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय आदि को सांप सूंघ सकता है। यकीन न हो तो केंद्र सरकार के उस रवैये पर गौर करें जो उसने 60 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले दूरसंचार मंत्री ए. राजा के प्रति अपना रखा है।

इस पर खास तौर पर गौर करना चाहिए कि उन्हें कोई और नहीं खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्लीनचिट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे अधिक शर्मनाक और कुछ हो सकता है कि राजा का जो कृत्य स्वतः घोटाला होने के प्रमाण दे रहा है उसका बचाव खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। माना कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व वाली केंद्रीय सत्ता चलानी है और इसके लिए द्रमुक का सहयोग जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि देश जीती मक्खी निगल ले। यद्यपि प्रधानमंत्री सीबीआई को बड़ी मछलियां पकड़ने की सलाह दे चुके हैं और भ्रष्टाचार को एक गंभीर समस्या बता चुके हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह बिहार सरकार के उस विधेयक के प्रति गंभीर क्यों नहीं जो केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है और जिसमें भ्रष्ट सेवकों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मधु कोड़ा और ए.राजा के कारनामे यह भी बताते हैं कि ठगी—गबन करने वालों अथवा खुले आम डाका डालने वालों को अब राजनीति में प्रवेश कर मंत्री—मुख्यमंत्री पद पाने की कोशिश करनी चाहिए।

इसके बाद वह राजा जैसी हरकत भी कर सकते हैं और मधु कोड़ा जैसी भी। गठबंधन राजनीति के इस दौर में वे इसके प्रति आश्वस्त रह सकते हैं कि उनके भ्रष्ट आचरण के बावजूद उन्हें कोई न कोई समर्थन देने के लिए उठ खड़ा होगा। आश्चर्य नहीं कि ऐसा करने वालों में खुद प्रधानमंत्री भी हों।

देश के नीति–नियंताओं को यह देखकर चुल्लू भर पानी की तलाश करनी चाहिए कि कोई दो हजार करोड़ के वारे–न्यारे कर रहा है और कोई 60 हजार करोड़ के। एक ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग महज 30–40 रुपये प्रतिदिन पर गुजर–बसर करने के लिए विवश हैं वहां हजारों करोड़ की हेराफेरी एक झटके में हो रही है और सत्ता के शीर्ष केंद्र में एक पत्ता तक नहीं खड़कता। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होता हो उसे धिक्कार, लेकिन जो शासक यह सब होते हुए भी मौन धारण किए हों उन्हें धिक्कारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे या तो संवेदनहीन हो चुके हैं या फिर भ्रष्ट तत्वों के संरक्षक–समर्थक। सवाल सिर्फ कोड़ा और राजा की कारगुजारियों का ही नहीं है, सत्ता के गलियारों में उनके जैसे लोगों का ही बोलबाला है। अब इसमें संदेह नहीं कि खोटे सिक्कों ने अच्छे सिक्कों को निष्प्रभावी बना दिया है। ए. राजा का बचाव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही नहीं, कांग्रेस के अन्य अनेक नेता भी कर रहे हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप का यह मतलब नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है।

आखिर क्या मतलब है इस कथन का? कहते हैं कि कोड़ा खदानों का पट्टा देने के एवज में 150–200 करोड़ वसूलते थे। चूंकि कोड़ा दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति इकट्ठा करने में सफल रहे इसलिए यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि देशी–विदेशी कंपनियों ने उन्हें खुशी–खुशी भारी भरकम रिश्वत दी। इसका एक अर्थ यह भी है कि उन्हें खदानों के पट्टे कौडियों के मोल मिल गए, ये वे स्थितियां हैं जिनमें नक्सलियों को अपने समर्थक जुटाने के लिए जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं। निःसंदेह हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकतीए जो कि नक्सलियों की रणनीति का प्रमुख अंग बन गई है, लेकिन क्या सत्ता के शिखरों पर बैठे लोगों के पास इसका कोई जवाब है कि देश में कुछ लोग रातों–रात करोड़ों रुपये क्यों बटोर ले रहे हैं? ऐसा करने वालों में कोड़ा एवं राजा तो उदाहरण भर हैं, क्योंकि न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अनुचित–अनैतिक तरीके से तिजोरियां भर रहे हैं और हमें–आपको पता नहीं। ■

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

प्रदेश के लिए एक काम हाथ में लें : शिवराजसिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने कहा है कि प्रदेश का हर नागरिक सप्ताह में दो घंटे भी अपने राज्य के लिए निकाल ले तो इसकी तस्वीर बदल जाएगी। सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा अपना मप्र अभियान पूरी तरह गैर राजनीतिक है और वे चाहेंगे कि राज्य का हर दल व हर नागरिक इसमें भागीदार बने।

मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश या प्रदेश का विकास केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। समाज भी साथ खड़ा हो तो विकास की गति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। आम आदमी में जुनून पैदा होना चाहिए कि यह प्रदेश मेरा है, मुझे इसे गढ़ना और बनाना है।

हर नागरिक अपना कर्तव्य पूरा करने लगे तो चमत्कार हो सकता है। हम रोजमर्रा के कामों के अलावा प्रदेश हित का कोई भी एक काम हाथ में लें। ये पौधे लगाने, पानी बचाने, बिजली बचाने, साफ–सफाई, नशामुक्ति जैसा कोई भी काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार स्थापना दिवस को अपना मध्यप्रदेश के संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश और यहाँ के विकास को लेकर लोगों के मन में अपनत्व का भाव जगाना है। सरकारी अमले में भी बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब धान 22 पसेरी वाला हिसाब है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।

कानून बनेगा : जनता के साथ ही प्रशासन को भी जवाबदार बनाने के लिए प्रदेश सरकार सूचना के अधिकार कानून से भी आगे बढ़कर सिटीजन चार्टर कानून लाने जा रही है। इसमें कोई भी काम करने की समय सीमा तय होगी और काम न होने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान भी रहेंगे।

साभार : रा. पत्रिका

राज्य स्तर पर कर्मचारियों के लिए पुरस्कार स्थापित करने के अलावा हम हर विभाग में माह का श्रेष्ठ कर्मचारी घोषित कर उसे सम्मानित करने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ठीक से काम नहीं करते उनके लिए दंडात्मक प्रावधान भी होंगे।

बस एक सकारात्मक खबर : मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वही लोगों का मानस बनाता है। हम चाहेंगे कि मीडिया अपने स्तर पर प्रदेश हित से जुड़ा कोई अभियान जरूर चलाए। ज्यादा कुछ नहीं तो रोज एक सकारात्मक खबर तो दी ही जा सकती है। ■

नक्सली हिंसा की चुनौती

ân;ukjk;.k nhf{kr

लेनिन ने कहा था–प्रत्येक क्रांति का मुख्य प्रश्न राजसत्ता का प्रश्न होता है। सभी राजनीतिक विचारधाराएं जनसमर्थन जुटाती हैं, सत्ता चाहती हैं। नक्सलपंथी हिंसा का लक्ष्य भी सत्ता है। वे हिंसाए हत्या और हमलों के जरिए सत्ता पर कब्जे की तैयारी में हैं। वे स्वयं को गरीब वर्ग और पूंजीपति व सत्ता अधिष्ठान को शोषक ''वर्ग–शत्रु'' जानते हैं। वे इसी वर्गशत्रु के सफाये में विश्वास रखते हैं। माओवादी/नक्सली संसदीय जनतंत्र में यकीन नहीं रखते। चुनाव से जुड़े वामपंथी भी संविधान और चुनाव तंत्र को पवित्र नहीं मानते, लेकिन वे इनका दुरुपयोग करते हैं। बाकी अधिकांश दल संविधानवाद के भीतर जाति, पंथ, मजहब, माफिया और धनबल जैसे तमाम अवैध तरीके अपनाकर सत्तावादी हैं।

भारतीय राजनीति की ''साख'' लगभग खत्म हो चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी और गरीब इस राजनीति और राज्यव्यवस्था से निराश हैं। संवैधानिक संस्थाएं उन्हें धीरज नहीं देतीं। वे राष्ट्र–राज्य के विरुद्ध युद्धरत हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्य नक्सली हिंसा की चपेट में हैं। सुरक्षाकर्मियों सहित 3000 से ज्यादा जानें गई हैं। वायुसेना हवाई हमले की अनुमति मांग रही है। केंद्र अनिर्णय की स्थिति में है। भारतीय राष्ट्र–राज्य ऐसा कमजोर कभी नहीं रहा।

नक्सली हिंसा कोई ताजा घटना नहीं है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव के स्थानीय जमीदारों के अत्याचारों के खिलाफ युवाओं के हथियार उठेए सीधा संघर्ष हुआ। कामरेड चारू मजूमदार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर आंदोलन की अगुवाई की। 1969 में सीपीआई का गठन हुआ। नक्सलबाड़ी गांव से उठी आवाज नक्सलपंथ बन गई। हिंसक गतिविधियों ने पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। तब कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे। नक्सलपंथ के खात्मे का निर्णय हुआ। जुलाई–अगस्त 1971 में सेना के कोई 40 हजार नौजवान तैनात किए गए। सेना ने घेराबंदी की। पुलिस और अन्य बलों ने धरपकड़ की। 45 दिनों की मशक्कत से ही सारा काम पूरा हो गया। पुलिस ने 1972 में चारू

> ***नक्सली हिंसा कोई ताजा घटना नहीं है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव के स्थानीय जमीदारों के अत्याचारों के खिलाफ युवाओं के हथियार उठेए सीधा संघर्ष हुआ। कामरेड चारू मजूमदार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर आंदोलन की अगुवाई की। 1969 में सीपीआई का गठन हुआ। नक्सलबाड़ी गांव से उठी आवाज नक्सलपंथ बन गई। हिंसक गतिविधियों ने पूरी व्यवस्था को चुनौती दी।***

मजूमदार को पकड़ा, उनकी मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई। पुलिस हिरासत में मृत्यु किसी भी राष्ट्र–राज्य के लिए जघन्य पाप है, लेकिन भारतीय पुलिस अक्सर ऐसे ही पराक्रम करती रहती है। एक साल पीछे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछाने की घटना हुई। पुलिस ने तलाशी के बहाने पराक्रम दिखाया, लालगढ़ के आदिवासी बेतहाशा उत्पीड़ित किए गए।

पुलिस अत्याचार राज्य प्रायोजित हिंसा होते हैं। छत्रधर महतो ने पुलिस अत्याचार विरोधी कमेटी बनाई, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार के दोषी पुलिसजनों पर कार्रवाई की मांग की गई। महाश्वेता देवी सहित अनेक बुद्धिजीवी भी शामिल थे, लेकिन राज्य सरकार ने जनतांत्रिक मागों को ठेंगा दिखाया। पुलिस इस आंदोलन से चिढ़ गई। उसने आंदोलन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संगठन को माओवादी बताया। बुद्धिजीवी भी गिरत में थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी बीच में आ गईं। महतो जेल में हैं। पुलिसिया उत्पीड़न ने गरीब आदिवासियों को माओवादी पलटन में ठेलने का काम किया। माओवादी हिंसा के दो साफ निष्कर्ष हैं। पहला, भारतीय राष्ट्र–राज्य 21वीं सदी में भी आंतरिक सुरक्षा का मजबूत तंत्र नहीं बना पाया। दूसरा, भारतीय राजनीति में आदिवासियों, वनवासियों, वंचितों के लिए कोई मौलिक जगह नहीं है। सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थाएं और मोटा सरकारी अनुदान लेने वाले एनजीओ भी आदिवासियों वंचितों में काम नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बेशक इन उपेक्षित क्षेत्रों में भी वनवासी कल्याण आश्रम व सैकड़ों शिक्षण संस्थाएं खोली हैं।

राष्ट्र–राज्य की सभी संस्थाएं अपनी साख खोती जा रही हैं। आंतरिक सुरक्षा ध्वस्त है। केंद्र आतंकवाद से भी लड़ते समय तुष्टीकरण रुख अपनाता है, वह नक्सलपंथियों से भी निपटने के काम में लचर है। कभी वह इसे कानून एवं व्यवस्था की समस्या बताता है और पूरी जिम्मेदारी राज्यों पर टरका देता है। कभी वह हास्यास्पद तरीके से इसे विकास की समस्या बताता है। प्रधानमंत्री ने मुंबई में कहा कि केंद्र नक्सलवाद को कानून एवं व्यवस्था का विषय नहीं मानता। वस्तुतः यह सामाजिक–

आर्थिक समस्या है। संप्रग सरकार माओवादी हिंसा पर सुस्पष्ट नहीं है। इसीलिए उसकी कार्ययोजना और रणनीति भी सुस्पष्ट नहीं है। नक्सली हमले धारावाहिक हैं। केंद्र सरकार ने विकास की खामी दूर करने के लिए अब तक क्या किया।

केंद्रीय बजट में मजहबी आधार पर करोड़ों रुपये के प्रावधान हुए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार देनेए ढाचागत सुविधाएं खड़ी करने और आदिवासियों, वंचितों, गरीबों को भी उदारीकृत अर्थव्यवस्था का हिस्सा देने के लिए सरकार ने क्या किया।

प्रधानमंत्री ने पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन में भी नक्सली हिंसा को बड़ी चुनौती बताया था। केंद्र तबसे एक इंच भी आगे नहीं चला। प्रधानमंत्री अभी भी असमंजस में हैं। पुलिस अधिकारियों के सिर कलम किए जा रहे हैं। उनके अपहरण हो रहे हैं, उनकी आखें फोड़ी जा रही हैं। इस वातावरण में पुलिस के लिए नक्सलियों को मात्र प्रथम द्रष्टया आरोपी देखना और अपनी जान गंवा देना आसान कर्तव्य नहीं है। सिर्फ झारखंड में ही 329 से ज्यादा पुलिस कर्मी मारे जा चुके हैं। नक्सली आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं। पुलिस कानून से बंधी है, उस पर मानवाधिकार के बंधन हैं। वे हमलावर हैं। सेना के हेलीकाप्टरों पर हमले हैं। बावजूद इसके केंद्र अब तक कोई ठोस कार्ययोजना भी नहीं बना पाया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासी दोहरी–तिहरी मार खा रहे हैं। नक्सली उन्हें पुलिस का मुखबिर मानकर पूछताछ करते हैं, अंगभंग करते हैं, महिलाओं का भी शोषण करते हैं। पुलिस उन्हें माओवादी मानकर पीटती है, अवैध हिरासत में रखती है। सरकार से निराशा है। दो तरफा अत्याचारों से पीड़ित नवयुवक माओवादियों के साथ हो लेते हैं।

संप्रग ने भारत पर शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। अब भी समय है, केंद्र देश के आंतरिक शत्रुओं से संघर्ष की ठोस कार्ययोजना बनाए। सेना के इस्तेमाल से बचे, सेना का इस्तेमाल माओवादियों की ताकत बढ़ाएगा। पुलिस आमजनों के उत्पीड़न से बचे। उत्पीड़ित आमजन माओवादी समूह में भर्ती का विकल्प चुनते हैं। आदिवासियों, वंचितों, आमजनों को राजनीति की मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्र संकल्प तो करे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता।

भारतीय राज्य विफल हो गया है। केंद्र अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाया। शासन के अधिकार में देश की अंतर–वाह्य सुरक्षा के प्राथमिक कर्तव्य हैं। आखिरकार केंद्र का संकट क्या है, देश के दोनों बड़े राष्ट्रीय दल और कमोबेश पूरा राजनीतिक तंत्र नक्सलपंथ से लड़ने में सरकार के साथ है। भाजपा ने पहले ही सख्ती की मांग की थी। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। कमी केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। आश्चर्य है कि संविधान, कानून, सेना और पुलिस बल से लैस बहुमत प्रतिपक्ष के समर्थन के बावजूद निर्दोषों और पुलिस बलों की हत्याएं टुकुर–टुकुर देख रहा है और मुट्ठी भर कमजोर नक्सली भारतीय राष्ट्र–राज्य को चुनौती दे रहे हैं। संप्रग ने भारत पर शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

अब भी समय है, केंद्र देश के आंतरिक शत्रुओं से संघर्ष की ठोस कार्ययोजना बनाए। सेना के इस्तेमाल से बचे, सेना का इस्तेमाल माओवादियों की ताकत बढ़ाएगा। पुलिस आमजनों के उत्पीड़न से बचे। उत्पीड़ित आमजन माओवादी समूह में भर्ती का विकल्प चुनते हैं। आदिवासियों, वंचितों, आमजनों को राजनीति की मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्र संकल्प तो करे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। ■

(लेखक उप्र सरकार के पूर्व मंत्री हैं)

पृष्ठ 13 का शेष

बढ़ती महंगाई विशेष मुद्दे होंगे जिनके कारण आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है।

⏭ **राज्य चुनाव में भाजपा गठबंधन की स्थिति क्या है?**

भाजपा और जद(यू) का एनडीए गठबंधन मिल कर चुनाव लड़ रहा है। हम स्थानीय रूप से अन्य किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं।

⏭ **चुनावों में महिलाओं और युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आप क्या कर रहे हैं?**

हमने महिलाओं और युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। आज तक फाइनल की गई 59 सीटों में से 7 महिलाएं और 20 युवा वर्ग के लोग है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। नामांकन बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुए हैं और पार्टी में सभी इससे संतुष्ट हैं।

⏭ **क्या भाजपा मई में लोकसभा चुनावों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के रिकार्ड को विधानसभा चुनावों में भी कायम रख सकेगी?**

गत लोकसभा में जैसा रूझान रहा है, निश्चित ही उससे बेहतर प्रदर्शन का प्रयास रहेगा। लोकसभा में 'शून्य' प्रतिनिधित्व से उठ कर हमारी संख्या 8 तक जा पहुंची, जो हमने जद(यू) गठबंधन के साथ मिलकर लड़ी, जिसमें जद(यू) को एक सीट मिली, और इस प्रकार हम 2/3 सीटों पर जीते।

⏭ **चुनाव लड़ने में पार्टी कितनी एकजुट है?**

पार्टी पूरी तरह एकजुट है ताकि राज्य में सरकार बनाने में निर्णायक विजय मिले। लोगों का निर्णय है कि भाजपा सत्ता में लौटे ताकि उनके दुखों का अंत हो और प्रगति तथा समृद्धि के एक नए युग की शुरूआत हो सके। ■

नक्सलवाद के खिलाफ ठोस रणनीति बनाने की जरूरत : प्रकाश जावडेकर

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा 28 अक्टूबर, 2009 को जारी प्रेस वक्तव्य

Vब यह सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि नक्सलवादियों ने देश के साथ युद्ध छेड़ रखा है। जिस भयंकरता और निरन्तरता के साथ नक्सलवादी पूर्व निश्चित लक्ष्यों पर प्रहार कर रहे हैं, उससे उनके कुत्सित इरादों का साफ पता चल जाता है। अब किसी के भी दिमाग में इस बारे में शक नहीं रहना चाहिए कि नक्सलवादी एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते वे भारत के संविधान को भी मान्यता प्रदान नहीं करते है और अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा को एक हथियार के रूप में प्रयोग करने पर तुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादियों द्वारा किए गए हमलों की घोर भर्त्सना करती है तथा सरकार को चेतावनी देती है कि यदि वह इस खतरे को काबू में करने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू नहीं करती है, तो देश के लिए यह नक्सली खतरा भयंकर रूप ले सकता हैं।

पश्चिम बंगाल में राजधानी एक्सप्रेस को बंधक बनाए जाने से संकेत मिलता है कि नक्सलवादी इस कदम को जन–आंदोलन के रूप में पेश करने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं। विगत तीन मास के दौरान नक्सलवादी महाराष्ट्र में 15–16 और 17 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। उन्होंने पलामू, झारखंड, उड़ीसा और देश में अन्य कई जगह पुलिसकर्मियों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी। उन्होंने भाजपा सांसद के पुत्र पर हमला करके उसको तथा देश के कई भागों में आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। त्वरित कार्रवाई करके वे नक्सलवादी बैल्ट में जोकि 10 राज्यों के लगभग 167 जिलों में फैली हुई है, आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और प्रशासन को आतंकित करना चाहते हैं।

यह पूरी तरह साफ है कि नक्सलवादी इन जिलों में कोई विकास कार्य नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इससे उनके आंदोलन में बाधा पड़ेगी। वे अपनी लड़ाई के लिए आदिवासियों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, मानव अधिकारों के तथाकथित कार्यकर्ता जो अन्य अवसरों पर भारी हो–हल्ला करते हैं, इस हिंसा तथा सामान्य जनों की ऐसी जघन्य हत्याओं पर मौन बने हुए हैं।

राष्ट्र इस संकट से निपटने के लिए सरकार की कार्य योजना की जानकारी चाहता है। इस खूनी जंग को जीतने के लिए भाजपा तितरफा कार्रवाई किए जाने की मांग करती है। पहले, यह कि अविलंब समन्वित पुलिस कार्रवाई की जाए। दूसरे, यह कि उनके बाहरी संपर्क काट दिए जाएं। तीसरे, यह कि आदिवासियों को न्याय देने के लिए विकास कार्यक्रम यथासंभव शीघ्र समुचित रूप में चलाए जाएं। ■

स्पेक्ट्रम मामले को लेकर संसद में सरकार को घेरेगी भाजपा

भाजपा प्रधानमंत्री जी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करती है कि क्या उन्होंने 2–जी स्पेक्ट्रम को स्वीकार करने की अनुमति दी है या नहीं। ऐसा किया जाना तत्कालीन विधि मंत्री एच.आर. भारद्वाज की नोटिंग में हुए नए खुलासे और प्रधानमंत्री के संचार मंत्री को लिखे पत्र और संचार मंत्री के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र से हुए नए खुलासे को देखते हुए जरूरी है।

नए खुलासे से स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री जी ने उस मामले में 2–जी स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसमें ऐसा किया गया है। "पहले आओ पहले पाओ" के आधार का मुद्दा और 2008 में बिक्री हेतु स्पेक्ट्रम के 2001 में मूल्यन के दोनों मुद्दे विवादास्पद हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त ने इन मुद्दों पर सटीक जांच करने का सीबीआई को आदेश दिया है। प्रधानमंत्री जी ने संचार मंत्री श्री राजा की कार्रवाई का सार्वजनिक रूप में समर्थन किया है। भाजपा प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है कि उनके 2 नवम्बर, 2007 के पत्र का अनुसरण क्यों नहीं किया गया था, जिसमें श्री राजा से 2–जी स्पेक्ट्रम पर सभी कार्रवाई बंद करने को कहा गया था। जो बचाव किए जाने के योग्य नहीं है, उसका बचाव करके प्रधानमंत्री जी अपनी छवि को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि सामने दिखाई दे रही लूट का प्रधानमंत्री जी द्वारा बचाव किया जा रहा है, किसी अन्य के द्वारा नहीं।

भाजपा संसद के आगामी सत्र में इस विषय को उठाएगी और सरकार से इस बारे में ठोस कार्रवाई करने की मांग करेगी। ■

जब सरकार ही कहे बढ़ेगी महंगाई तो नियंत्रण कौन करेगा?

महंगाई से जूझ रहे लोगों को खाने–पीने की चीजों के दाम में निकट भविष्य में कोई राहत मिलती नहीं दिखती। एक दिन पहले ही सरकार ने खुद माना था कि इस साल खरीफ सीजन में अनाज की पैदावार में दो करोड़ टन से अधिक की कमी आई और दूसरे ही दिन खाद्य और कृषि मंत्री शरद पवार ने भी कहा कि हालात तभी सुधरेंगे, जब अगले साल रबी सीजन की पैदावार बाजार में आएगी। पवार का आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में यह कहना एक गैर जिम्मेदाराना बयान ही माना जाएगा। दरअसल देश में खाद्य पदार्थों की सप्लाई के मोर्चे पर जो किल्लत पैदा हुई है वह सरकार की लचर कृषि नीति का नतीजा है। चाहे समर्थन मूल्य का मामला हो या आयात के फैसले या फिर कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह का। हर मोर्चे पर नीति–निर्माता नाकाम साबित हुए हैं। दाल और चीनी की आसमान छूती कीमतें इसका उदाहरण है।

17 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में खाद्य पदार्थों के थोक मूल्यों में पिछले साल की तुलना में 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। दालों की कीमतें

→

चीनी, दूध, आटे व दालों से बिगड़ गया बजट

चीनी, दूध, आटे और दालों की तेजी ने आम उपभोक्ता की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। उड़द दाल की कीमतों में पिछले दो महीने में 35 फीसदी, मूंग की कीमतों में 31 फीसदी और अरहर दाल की कीमतों में दस फीसदी की तेजी आ चुकी है। इस दौरान चीनी की कीमतों में लगभग 22 फीसदी दाम बढ़ चुके हैं। आटे के दाम पिछले एक महीने में 20 फीसदी और दूध के 7.6 फीसदी बढ़े हैं। फुटकर बाजार में अरहर दाल का भाव बढ़कर 89 रुपये, उड़द का 80 रुपये, मूंग का 83 रुपये, आटा 18 रुपये और चीनी का दाम बढ़कर 39 प्रति किलो हो गया। फूल क्रीम दूध के दाम बढ़कर 28 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चालू खरीफ सीजन में दलहन और चीनी के उत्पादन में कमी आने की आशंका है इसलिए हाल–फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत मिलनी मुश्किल है। महंगे आयात से पिछले दो महीने में घरेलू मंडियों में उड़द और मूंग के दाम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा बढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के प्रथम अनुमान के मुताबिक उड़द का उत्पादन 8.8 लाख टन और मूंग का 5.2 लाख टन होगा। वर्ष 2008–09 खरीफ में उड़द का 8.3 और मूंग का 7.7 लाख टन का उत्पादन हुआ था। ऊंचे भाव आने की संभावना से पिछले एक महीने में गेहूं की कीमतों में 225 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। इसका असर आटे की कीमतों पर पड़ रहा है। आटे के दाम अक्टूबर महीने में 15 रुपये प्रति किलो थेए जो कि बढ़कर 18 रुपये प्रति किलो हो गये हैं। घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता में कमी और वर्ष 2009–10 में गन्ना पेराई सीजन में देरी से चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सितंबर के शुरू में चीनी के भाव 32 रुपये प्रति किलो थे, जो कि बढ़कर 39 रुपये प्रति किलो हो गये हैं। हाल ही में मदर डेरी ने फुल क्रीम दूध की कीमतों में दो रुपये बढ़ाकर भाव 28 रुपये प्रति किलो कर दिये हैंए जब कि दो महीने पहले अमूल ने दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। ■

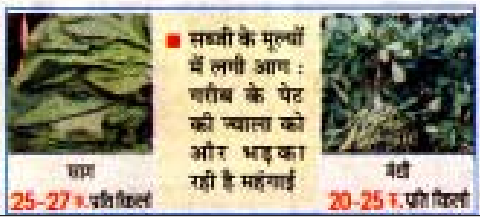

23 फीसदी बढ़ गई हैं। ये बढ़ोतरी थोक मूल्यों में है। खुदरा खरीदार के लिए ये कीमतें कहर बन कर टूटी हैं। इस पर चावल के उत्पादन में डेढ़ और गन्ने के उत्पादन में 2.18 करोड़ टन की कमी आने का अनुमान है। इसी वजह से शरद पवार कह रहे हैं कि रबी सीजन की फसल आने तक महंगाई कम होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दरअसल खाद्य पदार्थों के इस संकट की जड़ नीतिगत मसलों पर विफलता ही है। पैदावार का गलत अनुमान से लेकर आयात और निर्यात के गलत फैसलों से ही खाद्यान्न कीमतों का यह संकट खड़ा हुआ है। पैदावार के गलत अनुमान और निर्यात के गलत फैसलों से चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन लगता है अब भी इन फैसलों से सबक नहीं लिया गया है।

गन्ना मूल्य के निर्धारण के लिए एफआरपी नाम की जो नई व्यवस्था अपनाई गई है, उससे सीधे–सीधे चीनी मिल मालिकों को फायदा होने जा रहा है और किसानों को भारी घाटा। ऐसे में किसान किस दम पर गन्ने की खेती करेगा।

वैसे भी पिछले साल की तुलना में गन्ने का रकबा काफी घटा है। नीतियों में इन्हीं खामियों की वजह से देश में चीनी का उत्पादन घट कर 150 लाख टन रह गया है। ऐसे हालात में खाने–पीने की चीजों की कीमतें में कमी आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अगर सरकार को लोगों को बढ़ती महंगाई से बचाना है तो कृषि सेक्टर की विकास दर को बढ़ावा देने के लिए कोई दूरगामी नीति तय करनी होगी। पिछले कुछ साल से जिस तरह इस सेक्टर को नजरअंदाज किया जा रहा है वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। ■

महंगाई मार गयी!

dम बारिश होने के कारण एक तो कृषि उत्पादन कम हुआ, ऊपर से सरकार की अप्रभावशाली नीतियों के कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को रोका नहीं जा पा रहा। सरकार द्वारा खुले बाजार में चीजों को बेचने की नीति बुरी तरह असफल हो गयी है। परिणामस्वरूप गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। किसी ने ठीक कहा है कि अगर किसी का वेतन पांच हजार रूपये है और उसके परिवार में पांच सदस्य हैं तो उन्हें शायद एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ेगा। पिछले छह माह के दौरान रसोई के बजट में तीन गुणा वृद्धि हो गयी है। 'दाल–रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ' वाला गीत अब यादों में ही रह गया है। पहले दाल आम आदमी के बजट से दूर हुई तो अब आटा महंगाई होने के कारण रोटी भी छिन गयी है।

हर सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती है लेकिन मौजूदा हालात में तो दो जून की रोटी का सवाल ही सबसे बड़ा हो गया है। सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए वरना यह नहीं भूलना चाहिए कि भूखे पेट लोग किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं।

आटे की कीमत इन दिनों 22 रूपये प्रति किलो है तो चीनी 40 रूपये प्रति किलो जबकि 15 दिन पहले आटा 17 रूपये और चीनी 33 रूपये किलो थी। अंडे 40 रूपये दर्जन हैं जबकि मूंग धुली जैसी दालें 90 रूपये किलो। सर्दियों में लोग प्रायः दाल, साग आदि अन्य दालों में देसी घी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी कीमत भी अब 250 रूपये किलो से अधिक है। इसी तरह आलू 25 रूपये, मटर 70 से 80, प्याज 25 रूपये, घीया 20, नींबू 80, अदरक 50 और सेब सौ रूपये किलो बिक रहा है। गरीबों को खाजा केला 40 रूप्ये दर्जन है। ढाबों पर मिलने वाले खाने की प्लेट से सलाद गायब हो चुका है। ढाबा संचालकों की मानें तो सलाद पर आने वाला खर्च न तो वे उठा सकते हैं और न ही ग्राहक दे पायेगा। टमाटर, खीरा व मूली को ही एक साथ परोसा जाये तो एक किलो सलाद की कीमत 42 रूपये होगी, जो खाना खाने से भी महंगा रहेगा।

एक गृहिणी का कहना था कि रसोई का मासिक खर्चा चार हजार रूपये से बढ़कर सात हजार रूपये तक पहुंच गया है। परिणामस्वरूप उन्हें मनोरंजन पर होने वाले खर्च पर भारी कटौती करनी पड़ी है। इसका अर्थ तो यही है कि घर से बाहर न निकलो, कोई पिक्चर न देखो और यहां तक कि घर के लिए कोई नया सामान भी न खरीदो। बहरहाल दालों, चीनी और डेयरी उत्पादनों (घी–मक्खन आदि) की कीमतों में वृद्धि तो उनके कम उत्पादन के कारण हुई तो समझ आती है लेकिन दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि गेहूं की भारी फसल होने के बावजूद गेहूं की कीमतों में इतनी तेजी सरकार की कथित गलत नीतियों का ही परिणाम है। रिपोर्ट के अनुसार गेहूं का बड़ा हिस्सा तो सरकारी एजेंसियों ने खरीद लिया। किसानों और व्यापारियों के पास भंडारण के लिए ज्यादा गेहूं नहीं बची जिसके कारण वे गेहूं खुले बाजार में जारी नहीं कर पा रहे। सच्चाई यह भी है कि सरकार ने गेहूं की बिक्री के दाम पहले ही ज्यादा तय कर दिये हैं तो बाजार में उसकी कीमतें बढ़ना स्वाभाविक ही है। एक जमाना था जब कोई फकीर या भिखारी दरवाजे पर आता था तो घर वाले उसे भूखा नहीं जाने देते थे। दो रोटी तो उसे हर घर से मिल ही जाती थीं लेकिन अब परिवार के हर सदस्य को पूछ कर कि वह कितनी रोटियां खायेगा उसी हिसाब से चपाती बनायी जाती हैं ताकि एक भी चपाती फालतू न बने। ऐसे में उन लोगों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है जो दिहाड़ी पर काम करते हैं और चूल्हा जलाते हैं। दिहाड़ी न मिले तो पेट की आग में जलना पड़ता है। हर सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की बात करती है लेकिन मौजूदा हालात में तो दो जून की रोटी का सवाल ही सबसे बड़ा हो गया है। सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए वरना यह नहीं भूलना चाहिए कि भूखे पेट लोग किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। ■ (साभार)

पार्टी की विशिष्ट पहचान ही भाजपा की राजनीतिक पूंजी

7 एवं 8 नवम्बर 2009 को भोपाल में भाजपा मध्यप्रदेश कार्यसमिति की बैठक संपन्न हुयी। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुयी तथा देश एवं प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर सर्वसम्मति से राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। हम यहां बैठक का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर रहे हैं:–

संगठन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण हमारी प्राथमिकता : कैलाश जोशी

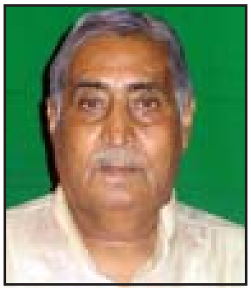

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद कैलाश जोशी ने मध्यप्रदेश में दोबारा पार्टी की सरकार बनने के लिए प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी नगरीय निकायों के चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन और पार्टी को विजयी दिलाने की चुनौती सामने है। लेकिन यह भी सुखद संयोग है। हमारे पास राज्य सरकार की आकर्षक जनोन्मुखी उपलब्धियां हैं। पार्टी और संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता और पार्टी के प्रशंसक हैं। उनके बलबूते पर नगरीय निकायों के चुनाव में सफलता प्राप्त होगी। आपने पार्टीजन और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे आने वाली चुनौतियों के प्रति सजग और तत्पर रहें। कैलाश जोशी बालाघाट में पार्टी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने की। डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने और वन्दे मातरम के गायन के साथ बैठक आरंभ हुई। कैलाश जोशी ने पार्टी के सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी लक्ष्य की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि हमें उन क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां अभी पार्टी संगठन ने पैठ नहीं बना पायी है। हम एक सुविचारित रणनीति के तहत उन क्षेत्रों में पहुंचें, और सभी वर्गों और जीवन के क्षेत्रों से जुड़े लोगों से रू–ब–रू होकर इनका विश्वास अर्जित करें।

कैलाश जोशी ने कहा कि हमारे ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने की है। इसके प्रति हमें हमेशा जागरुक और सजग रहना है। देश की निगाहें भाजपा पर टिकी है। वह हमें 'पार्टी विद डिफरेंस' के रूप में ही देखना चाहता है। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की साख और सम्मान पार्टी की इसी विशिष्टता पर निर्भर रही है कि जिसे बचाने के लिए हमें हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। संगठन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण हमारी प्राथमिकता और चिंता होना चाहिए। इसके लिए माननीय कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, प्यारेलाल खण्डेलवाल जैसों का उत्सर्ग पूर्ण जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। अनुकरणीय है।

नैतिक मूल्यों की स्थापना और सामाजिक न्याय हमारा परम लक्ष्य : नरेन्द्र सिंह तोमर

अपने अध्यक्षीय भाषण में नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता लक्ष्य नहीं है, सत्ता सामाजिक परिवर्तन और जनता की खुशहाली का साधन मात्र है। नैतिक मूल्यों की स्थापना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना हमारा परम लक्ष्य है, इसे निशियाम याद रखना है भाजपा का हर कार्यकर्ता पं.दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन का संवाहक है। विचारधारा से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता राज्य सरकार की नीतियों के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में विपुलता और समृद्धि लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। खुशहालीपूर्ण इस परिवर्तन का अहसास हमें अपने कार्यों और व्यवहार से आम आदमी को कराना है। उसे इन कार्यक्रमों से राहत महसूस होना चाहिए। तभी हमारे कार्यक्रमों की सार्थकता और सफलता सिद्ध होगी।

मंच पर अतिथियों कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, शिवराज सिंह चौहान, नरेन्द्रसिंह तोमर, माखनसिंह चौहान, कप्तानसिंह सोलंकी, थावरचंद गेहलोत, सत्यनारायण जटिया, सुमित्रा महाजन, बाबूलाल गौर, माया सिंह, भगवतशरण माथुर, अरविंद मेनन, विजेन्द्रसिंह सिसोदिया, चन्द्रमणि त्रिपाठी, गंगाराम पटेल, विनोद गौटिया, भूपेन्द्र सिंह, फग्गनसिंह कुलस्ते, रामोराम गुप्ता, अरविंद भदोरिया, बाबूसिंह रघुवंशी, अजयप्रताप सिंह, अंचल सोनकर, राजेन्द्र पाण्डे, सरिता देशपाण्डे, निर्मला भूरिया, गोविन्द मालू का पुष्पहारों एवं पुष्पगुच्छों से स्वागत वरिष्ठ मंत्री गौरीशंकर बिसेन एवं बालाघाट जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी

ने किया। तदोपरांत बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का तिलक लगाकर, शाल, श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। स्वागतोपरांत सृष्टि जायसवाल एवं सहयोगी बहनों द्वारा वंदेमातरम एवं स्वागत गीत की प्रस्तुति की गई।

बैठक हेतु कार्यालय भवन में प्रवेश के पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री माखनसिंह चौहान ने नवनिर्मित पं.दीनदयाल उपाध्याय भवन का लोकार्पण पूरे विधि विधान से वैदिक पूजन पाठ के साथ किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, नेतागण एवं जिला भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा की अपनी विचारधारा, सिद्धांत और अनुशासन है : सुंदरलाल पटवा

भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनैतिक दल है जिसका जनसंघ से लेकर भाजपा तक 58 वर्षो के दौरान विभाजन नहीं हुआ जबकि अन्य राजनैतिक दल चाहे कांग्रेस वामपंथी या अन्य विचार के दल हो उनके अनेक विभाजन हुये है। इसका एकमात्र कारण भाजपा की अपनी विचारधारा, सिद्धान्त और अनुशासन है। उक्ताशय के उद्गार भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुये वरिष्ठ मार्गदर्शक पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा ने अपने उद्बोधन में बालाघाट में व्यक्त किये। आपने कहा कि भारत की सभी राजनैतिक पार्टीयां खंडित हुई हैं लेकिन केवल भाजपा ही है जो अपने 58 वर्षों के दौरान कभी खंडित नहीं हुई। जब तक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा सिद्धांत, रीति–नीति के अनुरूप काम करता है तब तक वह पार्टी में रहता है क्योंकि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि जब तक देश के हर गरीब के आंखों से आंसू पोछकर भारत को विश्व गुरू का दर्जा पुनः नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सत्ता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमने लम्बा समय विपक्ष में रहते हुये जनता की सेवा की है। सत्ता की धरती बहुत चिकनी होती है पांव फिसलने में देर नहीं लगती । लेकिन वे भाग्यशाली होते है जिनके पैर टिक जाते है । हम राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को संभलकर पैर रखने की आवश्यकता है।

श्री पटवा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुये यह भी कहा कि महात्वकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन महात्वाकांक्षा ऐसी होना चाहिए जिससे पार्टी को कोई नुकसान न हो क्योंकि इस संगठन की नींव में ऐसे अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मेहनत और तपस्या है जिस पर अब यह संगठन रूपी महल खड़ा है। उन्होंने पुराने समय के संस्मरणों का स्मरण करते हुये क्षेत्र के स्थानीय वरिष्ठ जनों को याद करते हुये यह भी कहा कि इसी बालाघाट जिले की बात करें तो पहले हम बहुत पीछे थे, आज हम बहुत आगे हैं। 6 में से 4 विधायक है। पहले हमें समझौता करना पडता था। आज हमें हराने करने लिए सारे दल एकजुट हो जाते हैं। श्री पटवा ने आगाह करते हुये यह भी कहा कि पार्टी का तेजी से विस्तार हुआ है हम गांव–गांव पहुंचे है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जायें।

सरकार प्रदेश के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत : शिवराज सिंह चौहान

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने भी कार्यसमिति में अपने संबोधन में कहा कि अपने म.प्र. की जब तक आम आदमी के मन में ललक और तड़प नहीं होगी तब तक अपना म.प्र. बनाने का भाव पैदा नहीं हो सकता। इसके लिए एक वातावरण का निर्माण करना होगा जो हम कर रहें हैं। इससे आगामी 4 साल में प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। हमने राज्य में सड़क, बिजली पानी की बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की है। खेती को फायदे का धंधा, किसानों को बोनस, सुशासन के साथ अच्छा राज्य बनाने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के 1 लाख से अधिक आबादी वाले 105 शहरों को संवारने और उनके विकास के लिए राज्य सरकार विशेष योजना तैयार कर रही है। इसके लिए 10 कंस्लटेंट की भी नियुक्ति कर दी गई है। प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है। भू–माफियाओं एवं अन्य सभी माफियाओं के खिलाफ कडी कार्यवाही की जा रही है। बेईमानों और भ्रष्टाचारियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जायेगा चाहे वह कितने भी प्रभावी क्यों न हो। केरोसीन की कालाबाजारी एवं खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों पर रासुका की कार्यवाही की जा रही है । ग्वालियर चंबल संभाग को डाकुओं से मुक्त कराने में ज्यादा सफलता मिली है । सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है और अब किसी भी कीमत पर सर नहीं उठाने दिया जावेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी केन्द्र सरकार के भेदभाव के बावजूद प्रदेश अपने संसाधनों से इस समस्या से निपटने प्रभावी कदम उठा रही है।

श्री चौहान ने कहा कि देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है और उन्हें महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। जिस पर न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी है। नगरीय निकाय चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा के अधिक से अधिक जन प्रतिनिधि चुनकर आयेंगे ऐसा विश्वास है।

श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा किये जा रहे भेदभाव और मंदी के दौर में भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों को छटवां वेतनमान दिया। जिससे प्रदेश के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा है। बिजली के क्षेत्र में भी नये पावर प्लांट लग रहें हैं। इसका काम प्राइवेट कम्पनियों को भी दिया

शेष पृष्ठ 29 पर

राजनैतिक प्रस्ताव

सामाजिक परिवर्तन की दिशा में राज्य सरकार की प्रेरक भूमिका

मध्य प्रदेश की दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक के दूसरे दिन 8 नवंबर को सर्वसम्मति से राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जिसे प्रदेश महामंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत किया एवं इसका समर्थन प्रदेश महामंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। हम यहां प्रस्ताव का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं।

Hkk जपा प्रदेश कार्यसमिति गत सितम्बर माह में सम्पन्न हुये विधानसभा उपचुनावों में तेन्दुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में विजय प्राप्त होने पर तेन्दूखेड़ा की जनता एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस विजय के उपलक्ष्य में हृदय से धन्यवाद देते हुये बधाई देती है। उल्लेखनीय है कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे।

मध्यप्रदेश में पिछले माहों में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में राज्य सरकार ने प्रेरक की भूमिका का निर्वाह किया है। प्रदेश को विकसित, संपन्न, न्याययुक्त, पारदर्शी, नैतिक, भ्रष्टाचार मुक्त स्वर्णिम प्रदेश बनाने की दिशा में भाजपा सरकार कृत–संकल्पित है।

समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मा. शिवराज सिंह चौहान दृढ़–संकल्पित है। व्यापक प्रतिकूलताओं के बावजूद सरकार द्वारा प्रदेश में जो अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, उससे सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश सरकार अधोसंरचना, निवेश वृद्धि, खेती को लाभकारी बनाने, शिक्षा व स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त–दुरूस्त करने, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण करने, समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण, स्वशासन एवं विकास पर केन्द्रित योजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों को लागू करने में डटकर लगी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में समग्र परिवर्तन के लिए किये जा रहे प्रयत्नों की भाजपा कार्यसमिति भूरि–भूरि प्रशंसा करती है।

राज्य में पिछले 6 वर्षों के दौरान ग्रामीण सडक के अतिरिक्त, रिकार्ड सड़कों के निर्माण के साथ ही करीब 200 से अधिक उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण स्वयं के संसाधनों से कर रिकार्ड बनाया है। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़ने की कार्यवाही जारी है। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश के छोटे से छोटे सभी गाँव वर्ष 2013 तक बारह मासी सड़कों से जोड़ दिये जावेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के मामले में मध्य प्रदेश की गणना देश के अग्रणी राज्यों में की गई है। 1 करोड़ 12 लाख 85 हजार से अधिक जॉब कार्ड जारी कर 27 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार की गारंटी दी गई। 5 लाख 58 हजार 920 निर्माण कार्य स्वीकृत कर कार्य आरंभ हुए हैं, जिसमें से 60 हजार से अधिक कार्य पूर्ण किये गये है।

विद्युत क्षेत्र में राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधनों से उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के बिजली आपूर्ति मे सहयोग के बिना किसानों, उद्योगों एवं आम उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने का प्रयास किया गया है

प्रदेश में पिछले 5–6 माहों के दौरान 595 मिडिल स्कूलों की स्थापना की गई एवं 1785 अध्यापकों के नये पद स्वीकृत किये गये है। सरकार द्वारा व्यापक परीक्षा उतीर्ण 12 हजार से अधिक शिक्षा गारंटी शालाओं में पदस्थ गुरूजी, औपचारिकेत्तर शालाओं में पदस्थ अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है जो कि 10 वर्षों से दर–दर भटक रहे थे। प्रदेश के श्योपुर, सीधी, रीवा, शिवपुरी एवं डिण्डौरी जिलों में टेक्नीकल शिक्षा के लिये पाँच पॉलीटेक्निक कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिये उच्च न्यायालय ने भी मोहर लगाकर मध्यप्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बना दिया है। प्रदेश में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला पंचायत में लिये गये फैसलों पर अमल आरंभ होने से देश भर में मध्यप्रदेश की पहल अनुकरणीय साबित हुई है, जो देश भर में नजीर के रूप में चल पड़ी है।

प्रदेश में वर्ष 2002 की स्थिति में 7.7 लाख परिवार आवासहीन थे परंतु प्रदेश को मात्र 2.02 लाख आवासहीन परिवार मानकर अत्याधिक कम 59 हजार मकान का लक्ष्य दिया गया है । जबकि 5 वर्ष के लिये डेढ़ लाख से अधिक मकानों का लक्ष्य प्राप्त होना था । भारत सरकार के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण प्रदेश को करीब 1,00,000 लाख मकानों की राशि कम दी जा रही है ।

भाजपा कार्यसमिति देश में पिछले दिनों बढ़ी अत्यधिक कमरतोड़ मँहगाई की निंदा करते जनता से आव्हान करती है कि वह भाजपा द्वारा चलाये जा रहे महंगाई विरोधी आंदोलनों में बढ़–चढ़कर सहयोग करे और केन्द्र सरकार को बाध्य करे कि वह ''आम–आदमी'' को मँहगाई से निजात दिलाने हेतु गंभीर प्रयास करे।

इसके साथ ही कार्यसमिति भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करती है कि वह जनता के बीच पहुँचकर सक्रिय भूमिका निभाते हुये आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को विजयश्री दिलाने व स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण हेतु कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करें क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि यदि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच से होगा तो मध्यप्रदेश में सरकार के सहयोग से स्थानीय विकास में संघर्षों का प्रतिफल विकास के रूप में प्राप्त होकर स्वर्णिम मध्यप्रदेश की कल्पना साकार हो सकेगी। ■

बसों का किराया बढ़ाना आम जनता के साथ धोखा

fnल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 31 अक्टूबर को दिल्ली में 50 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन कर दिल्ली सरकार के डीटीसी का किराया बढ़ाए जाने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन का यह कार्यक्रम अलग–अलग विधानसभा के प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों को प्रदेशाध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, दिल्ली नगर निगम में भाजपा दल के नेता श्री सुभाष आर्य, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधायकों और निगम पार्षदों ने सम्बोधित किया। अनेक स्थानों पर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।

अक्षरधाम मंदिर के निकट पटपड़गंज विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली की मुख्यमंत्री का पुतला फूंका तथा सड़क के बीच धरना देकर यातायात को बाधित किया। प्रदर्शनकारियों को प्रदेशाध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने सम्बोधित किया। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा एक के बाद एक उठाए जा रहे जनविरोधी कदमों की कड़ी निन्दा की। प्रो. कोहली ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले बिजली पर से सब्सिडी खत्म की और फिर डीटीसी के किराए बढ़ाए और अब दूध की कीमतों में बढ़ोत्तरी की है। मंहगाई रोकने में पूरी तरह विफल हुई कांग्रेस सरकार आम आदमी पर लगातार आर्थिक बोझ लादती जा रही है। चुनाव के समय आम आदमी की दुहाई देने वाली कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो गया है और वह अब जल्दी ही पानी की दरों में भी बढ़ोत्तरी करने जा रही है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने एन्ड्रयूजगंज फ्लाईओवर के पास आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया और कहा कि शीला दीक्षित की सरकार आम आदमी को आर्थिक बोझ के तले लगातार दबाती जा रही है। डीटीसी की कुव्यवस्था और कुप्रबंधन को रोक कर तथा डीटीसी प्रशासन को चुस्त–दुरूस्त करके घाटे को कम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने में सरकार पूर्णतया विफल रही। घाटे की दुहाई देकर आम आदमी पर बसों के किराए की वृद्धि का बोझ लादना सर्वथा अनुचित है। एन्ड्रयूजगंज के कार्यक्रम को प्रदेश मंत्री आशीष सूद और सतीश उपाध्याय ने भी सम्बोधित किया।

सुभाष नगर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों को श्री सुभाष आर्य ने सम्बोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा दिल्लीवासियों से किए जा रहे विश्वासघात की कड़ी आलोचना की और कहा कि आम नागरिक सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का शिकार बना हुआ है। सुभाष नगर चौक पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई। करोलबाग में शंकर रोड पर प्रदेश महामंत्री श्री आर.पी. सिंह और जिला उपाध्यक्ष राजेश भाटिया के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।

तुग़लकाबाद में संगम विहार में कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री श्री रमेश बिधूड़ी ने किया।

दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने एक अलग बयान में मदर डेयरी द्वारा दूध के दामों में दो रूपए तक की बढ़ोत्तरी किए जाने की निन्दा की है। प्रो. कोहली ने कहा कि आम आदमी के काम में आने वाली रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। दूध के दामों में बढ़ोत्तरी से यह बोझ और बढ़ेगा। मंहगाई को नियंत्रित करने में पूर्णतया विफल रही कांग्रेस सरकार को अब आम आदमी की दुहाई देने का कोई नैतिक हक नहीं रह गया है। दूध के दाम बढ़ाने के कदम की भाजपा कड़ी निन्दा करती है।

डीटीसी के कुप्रबंधन के चलते हुयी किराये में वृद्धि : प्रो. कोहली

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने दिल्ली सरकार द्वारा डी.टी.सी. बसों के भाड़े में की गई भारी वृद्धि को लोगों पर, खासतौर से निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों पर, असह्य बोझ बताते हुए सरकार से भाड़ा वृद्धि के फैसले को वापिस लेने की माँग की है।

प्रो. कोहली ने कहा कि बसों के भाड़े में वृद्धि का उन परिवारों पर तो असाधारण बोझ पड़ेगा जिनके एक से अधिक सदस्यों को काम–काज के लिए और स्कूल कालेज जाने के लिए बस से सफर करना पड़ता है। जिन घरों से तीन–चार सदस्यों को बस से आना–जाना पड़ता है, वे इस भारी बोझ

आखिर क्या खाये और क्या पिये आम आदमी?

केन्द्र की यूपीए सरकार और दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने पहले बसों के किराये में बेतहाशा बढ़ोतरी और फिर दूध के दाम बढ़ाने के सरकार के फैसले ने चौतरफा मंहगाई की मार झेल रहे लोगों की कमर पूरी तरह तोड़ दी है आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या खाये और क्या पिये। विधानसभा और फिर आम चुनाव की मजबूरी के चलते सरकार पिछले काफी समय से कीमतें बढ़ाने के लिए कसमसा रही थी। इस मजबूरी से निकलने के बाद अब लोगों से जमकर वसूली की जा रही है। पिछले तीन–चार महीनों में यह चौथा मौका है जब आम आदमी के बजट पर कुठाराघात किया है। सरकारी सूत्रों और विशेषज्ञों के आकलन अभी मंहगाई कम होने की उम्मीद नहीं दिखाई देती।

जानकारों का कहना है कि अभी मंहगाई और बढ़ेगी जहां एक ओर रसोई गैस पर मिल रही सब्सिडी को वापस लेने के प्रयास चल रहे हैं वहीं दूसरी ओर पानी के दाम बढ़ाने पर रस्साकसी चल रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर एक बार फिर पेट्रोल–डीजल के दाम बढा दिये जायें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मदर डेयरी का कहना है कि उसने 13 महीनों के बाद दामों में बढ़ोतरी की है लेकिन यह नहीं बताती कि उसने पिछले अगस्त में ही डबल टोन्ड और स्किमड दूध की कीमतें बढाई थीं।

अब पारस और गोपालजी जैसी कंपनियों ने भी दाम बढ़ाने की रट लगा रखी है। डी एम एस भी ऐसे में पीछे कैसे रहेगा। पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय भंडार में बेची जा रही अरहर, मूंग और उड़द की दाल की कीमतें लगभग दो गुना बढ़ी हैं। वर्ष 2008 में अरहर की कीमत 46 रूपये प्रति किलोग्राम थी जो अब 89 रूपये हो गई है। मूंग 36.50 की बजाय 72.50 पर बेची जा रही है। जून 2008 में 28 रूपये किलो की चीनी 35 रूपये पर पहुंच गई है। आखिरी कब तक कमजोर मानसून और कम उत्पादन तथा आर्थिक मंदी का रोना रोकर आम आदमी को कमजोर किया जायेगा। लोगों का कहना है कि उन्हें दिन रात भागने के बाद भी घर चलाने में पसीने छूट रहे हैं। वह एक चीज के दाम में हुई बढ़ोतरी को अपने बजट में एडजस्ट करने वाला ही होता है कि दूसरी चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं।

दिल्ली देहात में हालत और खराब है, शहरी क्षेत्रों में कभी सरकार मदर डेयरी से सस्ती दाल बेचती है तो कभी चीनी लेकिन गांव में यह सुविधा भी नहीं है। दूध बेचने वाली डेयरियों और ग्वाले मंहगाई का हवाला देकर मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। वे गाय और भैंस का खालिस दूध देने के नाम पर अभी लोगों से 35 रूपये प्रति किलो की कीमत वसूल रहे थे अब मदर डेयरी के इस फैसले के बाद वह भी कीमत को और बढा देंगे। चुनाव के बाद मंहगाई का चाबुक सबसे पहले पेट्रोल–डीजल पर चला। इसके बाद अगस्त में बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी वापस ले ली गई। एक सितम्बर को अमूल कंपनी ने अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। अब डीटीसी ने भी अपने किराये में 70 फीसदी की भारी भरकम बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया, रही–सही कसर मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ा कर पूरी कर दी। दिल्ली मेट्रो भी किराया बढ़ाने वाली है।

सरकार और उद्योगपति यह कहते नहीं थकते कि भारत जल्द ही महाशक्ति बनने जा रहा है लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि जब देश की 70 प्रतिशत आबादी 20 रूपये प्रति दिन पर गुजारा कर रही है तो यह कैसे संभव होगा। अगर बाजार में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर नजर डाले तो आसानी ने समझा जा सकता है कि यह व्यक्ति 20 रूपये में क्या खा पी रहा होगा। मंहगाई का अजगर उसके सारे बजट को निगलता जा रहा है। दूध पीना तो गरीब आदमी ने पहले ही छोड़ दिया था अब लगता है उसे चाय पीने के भी लाले पड़ जायेंगे। राजधानी में लोगों का कहना है कि कभी सोचा नहीं था कि आलू भी 25 और 30 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदना होगा। पहले गरीब का भोजन कहीं जाने वाली दाल पर डाका पड़ा और अब उसी गरीब के आलू को भी उससे छीना जा रहा है। हरी सब्जियां आम आदमी की पहुंच से पहले ही बाहर थीं, अब आलू खरीदने से पहले भी आदमी को कई बार सोचना पड़ता है। ■

➡ को कैसे वहन कर सकेंगे।

प्रो. कोहली ने कहा कि एक ओर तो सरकार शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बढ़–चढ़ कर बातें करती है और दूसरी ओर स्कूल–कालेज के छात्रों को बस भाड़े के भारी बोझ तले दबा रही है। छात्रों और अभिभावकों दोनों में सरकार के इस कदम को लेकर भारी रोष है। सरकार ने बस भाड़े में वृद्धि करते समय स्लैब में भी परिवर्तन कर दिया है। पहला स्लैब केवल तीन किलोमीटर है। अधिकांश कामकाजी लोगों को और स्कूल–कालेज छात्रों को कई–कई किलोमीटर लम्बा सफर करना पड़ता है। तीन किलोमीटर का प्रथम स्लैब बहुत छोटा है।

प्रो. कोहली ने कहा कि आम तौर पर पहले डीजल–पैट्रोल के दाम बढ़ने पर किराया बढ़ाया जाता था, इस बार सरकार ने डी.टी.सी. के कुप्रबन्धन से होने वाले घाटे को कम करने के लिए किराया वृद्धि की है। लोग जानना चाहते हैं कि डी.टी.सी. को हो रहे भारी घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है और डी.टी.सी. का प्रबंधव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? ■

नई प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रारूप निवेश के लिए हानिकारक

करदाताओं को भी राहत नहीं

fdसी भी सरकार के लिए अपना कामकाज चलाने के लिए कर बहुत महत्व रखते हैं। कर–नियम ऐसे साधन होते हैं जिनसे सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करती है और अपने दिन–प्रतिदिन कार्यों एवं देश के आर्थिक विकास के लिए राजस्व इकट्ठा करती है। कराधानों के माध्यम से ही सरकार देश की आय के समान वितरण के लक्ष्य भी पूरा करने की कोशिश करती है। वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 बहुत पुराना हो चुका है और इस अवधि के दौरान इसमें 4500 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं। कर नियमों के बदलाव समय की जरूरत होती है। अब नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) सार्वजनिक बहस और टिप्पणी के लिए सामने आ चुकी है।

विगत में भाजपा चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर सदा ही अपना योगदान देता रहा है। इस विषय पर लाभप्रद चर्चा शुरू करने के लिए प्रकोष्ठ ने 23 अक्टूबर को स्कोप कम्पलेक्स, नई दिल्ली में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें सभी लोगों के लाभ के लिए इस संहिता पर एक परिचर्चा पत्र भी जारी किया गया।

उद्घाटन तथा सीए सुशील गुप्ता का परिचय कराने के बाद अतिथि वक्ता सीए राहुल गर्ग, सीनियर पार्टनर पीडब्ल्यूसी ने 'अंतर्राष्ट्रीय कराधान संहिता' के प्रावधानों के निहितार्थों पर प्रकाश डाला। श्री गर्ग के अनुसार इस संहिता से भारत में विदेशी निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसमें टीडीएस सम्बंधी ऐसे प्रावधानों हैं, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में टीडीएस अवरूद्ध हो जाएंगे उन भुगतानों पर भी असर पड़ेगा जिन पर कर नहीं लगाया जाना है। नीचे की श्रेणी में आने वाले टीडीएस प्रमाणपत्र सम्बंधी प्रावधान को हटा लिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन करते हुए ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। आंशिक नियंत्रण के आधार पर 'एसेसी' अर्थात् कर निर्धारिती के 'रेजीडेंश्यल स्टेटस' को दुरूह बनाया गया है जिससे उनकी ग्लोबल आय पर भी भारत में कर योग्य बना दिया गया है और ऐसा करने से 'ग्लोबल मर्जर और एक्वीजिशन' में बहुत बड़ी बाधा पड़ेगी। जनरल एंटी एवोइडेंस रूल्स (जीएआर) के प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें सीआईटी को प्राधिकार दिया गया है कि वह ऐसी किसी कारोबारी व्यवस्था को चलाने की इजाजत नहीं देगा, यदि उसकी राय में वह कारोबार कर लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया है तो यह प्रावधान भी घरेलू कम्पनियों तक के लिए बहुत ही कठोर बन जाएगा। इसी प्रकार के उद्गार एक और अतिथि वक्ता सीए गिरीश आहूजा ने भी प्रगट किए जो प्रत्यक्ष कर के विख्यात विशेषज्ञ हैं और वे कई संस्थानों के फैक्ल्टी के अतिथि प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम्पनियों की सकल परिसम्पत्तियों के लाभ पर कर के आधार पर जो कर लगाया जाता था उसके स्थान पर उनकी सकल सम्पतियों के मूल्यों पर 2 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जबकि एक लम्बी अवधि के लिए भारी पूंजी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। दूसरे, रूग्ण एवं घाटे में चलने वाली कम्पनियों के लिए वर्तमान में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है जिससे यह प्रावधान तो उनके लिए और भी कठोर रहेगा और रूग्ण कम्पनियों में बढ़ोतरी ही होती चली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि संहिता में जिस सरलीकरण का दावा किया जा रहा है, वह नहीं है, बल्कि इसमें बड़ी संख्या में परिभाषाएं भरी पड़ी हैं। अध्यायों के अंत में कुछेक कठिन खण्डों का मात्र पुनः समायोजन ही किया गया है। संहिता का अच्छी तरह से सम्पादन करने पर देखा गया है कि इसमें 380 से भी अधिक गलतियां हैं। 10,00,000 रूपए की आय पर कम कर का आकर्षक प्रावधान वास्तव में धोखा मात्र है और उससे कर देयता कम नहीं होगी क्योंकि गृह सम्पत्ति के किराए और गृहनिर्माण के ऋण पर ब्याज तथा पीपीएफ में निवेश सम्बंधी छूटों को वापस ले लिया गया है।

इस अवसर पर संहिता पर एक परिचर्चा पत्र भी जारी किया गया। इस पत्र को सीए राजकुमार अग्रवाल के संयोजन में प्रकोष्ठ की तकनीकी समिति ने तैयार किया है। प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक सीए गोपालकृष्ण अग्रवाल समिति के चेयरमैन रहे हैं जिन्होंने इस आयोजन की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में तथा दस्तावेज में भी उन्होंने कहा कि कराधान नीति देश के आर्थिक विकास में एक उपकरण के रूप में सहायक होनी चाहिए और यह ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग स्वेच्छा से इसका अनुपालन करें और इससे टैक्स जीडीपी अनुपात में वृद्धि हो। कर–निर्माता छूट और प्रोत्साहन 'सेक्टोरल' विकास और क्षेत्रीय संतुलनों में गति लाने के लिए उपयोग करते हैं, परन्तु यहां तो इन्हें वापस ले लिया गया है। यह संहिता तो सेक्टर, क्षेत्रों के बीच खाई कम करने में बुरी तरह बाधक बनेगी और एसएमई की प्रगति में रूकावट पहुंचेगी। इन प्रोत्साहनों के स्थान पर कुछ विशेष उद्योगों को छूट दी गई है जो बड़े–बड़े उद्योगों के क्षेत्र में आती हैं।

पूंजी बाजारों के लिए भी, विशेष रूप से म्युच्युल फंडों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। म्युचुअल फंडों के लाभांशों को कर योग्य बना दिया गया है जबकि इक्विटी लाभांशों को छूट दी गई है। यह प्रावधान छोटे निवेशकों को हानि पहुंचाएगा। गैर–लाभकारी संगठन (एनपीओ) पर अनुमत्य राशि से ऊपर की सकल प्राप्ति पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव है; इस आय पर कर लगाने से धर्मार्थ गतिविधियां चलाने वाले एनजीओ के लिए धन का अभाव हो जाएगा। 'धर्मार्थ गतिविधियों' का नाम बदल कर 'कल्याण गतिविधियां' रखा गया है, जिससे भ्रम ही पैदा होता है। लगता है कि यह संहिता सीबीडीटी संस्थान के महत्व को भी कम कर रही है। इसमें बहुत सी प्रशासनिक बाधाएं और रूकावटें शामिल हैं। हमारे इस परिचर्चा पत्र में केवल निहितार्थों पर चर्चा नहीं की गई है, बल्कि सुझाव भी दिए गए हैं।

मुख्य अतिथि श्री अरूण जेटली ने वित्त मंत्री के इरादों और इस प्रकार के महत्वपूर्ण कानून को लाने के उनके रवैये पर भी चर्चा की गई। किसी भी कानून बनाने की औपचारिकता के लिए आवश्यक है कि नीति निर्माता अर्थात् वित्तमंत्री को प्रारूपकार से दूरी बनाए रखनी चाहिए और दस्तावेज का सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए, परन्तु ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। दूसरे, इस संहिता में विगत सभी कोर्ट मामलों की उपेक्षा की गई है जो कि किसी भी कानून बनाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा आज की परिचर्चा पर सूक्ष्म विश्लेषण करेगी और इसे लोगों की आकांक्षाओं को समाहित करते हुए संसद के दोनों सदनों में ले जाएगी। उन्होंने प्रकोष्ठ, विशेष रूप से राष्ट्रीय संयोजक द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन की दक्षता पर गहन प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी कि वे पार्टी मंच पर 450 से अधिक शीर्ष प्रोफेशनल विशेषज्ञों को एकजुट कर पाए।

इस कार्यक्रम में बड़ी भारी संख्या में लोगों ने पहुंच कर अपनी प्रतिक्रिया दी। एशोशैम के प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष श्री मृदु हरि डालमिया (प्रमुख उद्योगपति) सम्मानीय अतिथि थे और उन्होंने देश के औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर अपनी बात रखी। श्रोताओं में अन्य प्रमुख हस्तियों में सीए सुभाष अग्रवाल, सीए एनसी माहेश्वरी, केन्द्रीय परिषद सदस्य सीए विनोद जैन और सीए सीजीएस नंदा, क्षेत्रीय परिषद सदस्य सीए सुधीर अग्रवाल, सीए भगवान दास गुप्ता (चेयरमैन एनआईआरसी) और सीए राजेश शर्मा, सीए अनिल गुप्ता और सीए प्रवीण कांत, श्री बीके सभरवाल (चेयरमैन एएनएमआई, एनआर) और भाजपा प्रदेश सीए प्रकोष्ठ संयोजक, सीए अखिलेश जैन म प्र, सीए संजय कपूर (पंजाब) और सीए सुमित मित्तल (झारखण्ड) शामिल थे। सीए अविनेश माटा ने धन्यवाद और आभार प्रदर्शन किया। ■

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

पृष्ठ 24 का शेष

जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि इन तमाम परिस्थितियों से जूझने और इन परिस्थितियों में भी अच्छे से अच्छा काम कैसे हो, अपना म.प्र. बनाने पर लगातार मंथन किया है, यह मंथन अद्भुत था। राज्य सरकार अपने सातों संकल्पों को पूरा करना चाहती है।

श्री चौहान ने अपने संबोधन के प्रारंभ में कहा कि संगठन ने पूरी ताकत के साथ सरकार का साथ निभाया है और हमारे वरिष्ठों ने समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान कर म.प्र. सरकार का साथ दिया है। इस कार्यसमिति में भी आमसभा में आने वाली जनता को निमंत्रण देकर बुलाना, भोजन के पैकेट भी घर–घर से एकत्रित करने के साथ ही मंत्रियों को कार्यकर्ताओं के घर–घर ठहराकर बड़ा काम किया है और हम सभी के लिये एक नई राह बनाई है।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अवगत कराया कि नगरीय निकाय चुनाव हेतु प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र तैयार किये जाने हेतु पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री बाबूसिंह रघुवंशी को चुनाव घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। प्राथमिक सदस्यता का कार्य 15 नवम्बर तक एवं सक्रिय सदस्यता का कार्य 30 नवम्बर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाये। उन्होंने यह भी बताया कि नगरपालिका स्तर पर महंगाई को लेकर 11 नवम्बर से 13 नवम्बर तक परिवार सम्पर्क अभियान चलाया जायेगा।

बैठक समापन पर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट में प्रदेश कार्यसमिति के आयोजन के लिए प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि निकट भविष्य में हम लोगों को राष्ट्रीय कार्यसमिति के आयोजन का अवसर भी प्रदान किया जाये । साथ ही श्री बिसेन ने पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए भी सभी आभार व्यक्त करते हुये कहा कि इसमें पूरा पैसा पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगा है। श्री बिसेन ने संकल्प व्यक्त करते हुये कहा कि वे कार्यालय के रखरखाव के लिए आजीवन 10,000 रूपये प्रतिमाह अपनी ओर से सहयोग राशि प्रदान करेंगे। ■
~~~~~~~~~~

केन्द्र सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हित साधना बंद करे : अरुण जेटली

X त 27 अक्टूबर 2009 को भारतीय जनता पार्टी, केन्द्रीय व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आर्थिक क्षेत्र एवं व्यापार जगत की ज्वलंत समस्याओं को लेकर तथा केन्द्र सरकार की व्यापारी विरोधी नीतियों के विरूद्ध संसद भवन मार्ग, नई दिल्ली पर एक विशाल धरना, प्रदर्शन, संसद मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें अन्य लोगों के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, डा. मुरली मनोहर जोशी, श्री अरूण जेटली, श्री रामलाल जी, श्री विजय गोयल, श्री केदारनाथ साहनी, श्री ओम प्रकाश कोहली, श्री जगदीश मुखी, श्री श्याम जाजू, श्री प्रवीण खण्डेलवाल आदि नेताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा देशभर से लगभग 5000 व्यापारी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। धरना की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व सांसद श्री श्याम बिहारी मिश्रा ने की तथा कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सह–संयोजक श्री घनश्यामदास अग्रवाल ने किया।

व्यापारी वर्ग का गलत नीतियों के विरोध में धरना

धरना को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र के बाद भारत में दूसरा बड़ा क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है, जिसपर लगभग देश की 32 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। देश के कुल राजस्व का 70 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व व्यापारी वर्ग एकत्र करके सरकारों को जमा कराता है। इसके अलावा देश में 72 प्रतिशत रोजगार एवं नौकरियां यही वर्ग देश को उपलब्ध कराता है। आपदा–विपदा के समय में भी लोग इसी समाज से मदद की अपेक्षा करते हैं। इसके बावजूद भी यह समाज आज कई प्रकार की जटिलताओं जैसे अधिकारियों के शोषण से तथा असंवैधानिक वसूली आदि से पीड़ित है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य में संसद में व्यापारी समाज की समस्याओं को भाजपा द्वारा जोरदार ढंग से उठाया जाएगा।

धरना को सम्बोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि आज व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। रोजाना रंगदारी, लूट–पाट, डकैती, हत्या अपहरण की ताबड़तोड़ घटनाओं से व्यापारी वर्ग आज सर्वाधिक परेशान एवं आहत है। पूरे देश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसका सबसे ज्यादा शिकार व्यापारी वर्ग ही होता है। यह भी सर्वविदित है कि देश का व्यापारी वर्ग देश की अर्थनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा देश की आर्थिक व्यवस्था का रीढ़ है। इस कारण वह वितरण व्यवस्था का प्रमुख अंग है। वितरण व्यवस्था के साथ–साथ देश में सामाजिक सेवा करने वाला आज यह समाज सबसे ज्यादा उपेक्षित एवं पीड़ित है।

धरना को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरूण जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियां चंद देशी–विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव में उन्हें लाभान्वित करने के लिए बन रही हैं जबकि देश की आम जनता के हितों की अनदेखी हो रही है। छोटे–खुदरा व्यापारियों के हितों की उपेक्षा से विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था खतरे में है। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुएं आयातित हो रही हैं, जिनका असर घरेलू उत्पादों पर पड़ रहा है। सरकार को इन विदेशी वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए।

धरना को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल ने कहा कि जब–जब कांग्रेस सत्ता में आई है देश में महंगाई बढ़ी है। महंगाई के लिए केन्द्र सरकार की कर–नीति और गलत सरकारी योजनाएं जिम्मेदार हैं। एक तरफ तो देश की जनता इस महंगाई से घुन की तरह पीस रही है, तो दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग भी इससे खासा त्रस्त है। सरकार महंगाई को कम कर पाने में असमर्थ साबित हो रही है। केन्द्र सरकार इसके लिए व्यापारियों को ही दोषी मानती है और छोटे व्यापारियों के गोदामों पर छापे डालकर तथा उनके खिलाफ मुकइमें दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

धरना के बाद संसद मार्च किया गया। बाद में सैकड़ों व्यापारी प्रतिनिधियों के द्वारा गिरफ्तारियां दी गईं। श्री श्यामबिहारी मिश्रा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भी समर्पित किया गया। ■